रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2007/फाल्गुन 9, 1928
No. 53] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2007/PHALGUNA 9, 1928

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2007

सं. फा. 2(10)-बी (डी)/2007.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

बजट 2007-08

वित्त मंत्री, पी. चिदम्बरम का भाषण

28 फरवरी, 2007

अध्यक्ष महोदय,

मैं वर्ष 2007-08 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

I. अर्थव्यवस्था के संबंध में मध्यावधि रिपोर्ट

2. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने नवम्बर, 2006 में अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब मध्यावधि रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अनेक सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू हैं। अब मैं उन दोनों के बारे में विस्तारपूर्वक बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2004-05 में 7.5 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 में बढ़कर 9 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) हो गई और अग्रिम अनुमानों के अनुसार यह 2006-07 में 9.2 प्रतिशत हो गई है। इस प्रकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के तीन वर्षों में औसत वृद्धि दर 8.6 प्रतिशत रही। इस प्रभावकारी वृद्धि के फलस्वरूप दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित 8 प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य, 2002-03 में असंतोषजनक शुरुआत के बावजूद लगभग प्राप्त कर लिया जाएगा।

3. विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि का मुख्य आधार है और भविष्य के लिए इसके शुभ संकेत हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के तीन वर्षों में, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 प्रतिशत तथा आगे बढ़कर 11.3 प्रतिशत हो गई। सेवा क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि जारी है और इसमें इन तीन वर्षों में क्रमश: 9.6 प्रतिशत, 9.8 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

4. दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उतार-चढ़ाव हुए हैं। दसवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 2.3 प्रतिशत औसत वृद्धि होने का अनुमान है, जो 4 प्रतिशत वार्षिक के वांछित स्तर से कम है। लगभग 115 मिलियन परिवारों को कृषक परिवारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, इतनी अधिक जनसंख्या वाले देश को अनिवार्य खाद्य पदार्थों के मामले में लगभग पूर्णतया आत्मनिर्भर होना है, अन्यथा आपूर्ति संबंधी अड़चनें वृहत आर्थिक-स्थायित्व और वृद्धि संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार कृषि, नीति निर्माताओं के एजेंडा में सर्वोपरि

होनी चाहिए और हमारे संसाधनों के संबंध में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं थोड़ी देर में इसके संबंध में कुछ प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

आय तथा बचत

5. प्रगति रिपोर्ट से शुरुआत करते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि 2005-06 में प्रति व्यक्ति आय में, सही मायने में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बचत दर 32.4 प्रतिशत तथा निवेश दर 33.8 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है। मुझे आशा है कि ये उच्च वृद्धि दरें मौजूदा वर्ष में भी जारी हैं।

6. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार आर्थिक सुधारों, राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थायित्व के प्रति वचनबद्ध रही है।

7. राजस्व आय लगातार तीसरे वर्ष बढ़ी है। हमने अतिरिक्त राजस्वों का संग्रहण किया तथा माननीय सदस्य यह देखेंगे कि मैंने समग्र वृद्धि ईक्विटी और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को संवर्धित करने के लिए इन राजस्वों का सदुपयोग किया है, जो राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, इसके अध्यक्ष और प्रधान मंत्री के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।

मुद्रास्फीति की स्थिति

8. बैंक ऋण वर्ष दर वर्ष 2 फरवरी, 2007 तक 29.6 प्रतिशत बढ़ गया है। मुद्रा आपूर्ति (एम 3) 21.3 प्रतिशत तक बढ़ी है। विदेशी मुद्रा रिजर्व 180 बिलियन अमरीकी डालर है। यद्यपि ये उच्च वृद्धि की सहवर्ती विशेषताएं हैं, फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन मौद्रिक प्रवृत्तियों से कीमतों पर दबाव आया है। विश्व में वस्तुओं की विद्यमान कीमतों के स्तर से भी घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा है। साथ ही साथ गेहूं, दालों और खाद्य तेलों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं में आपूर्ति संबंधी अड़चनें सामने आई हैं। इसके परिणामस्वरूप, 2006-07 में औसत मुद्रास्फीति का अनुमान 5.2 और 5.4 प्रतिशत के बीच लगाया गया है, जो पिछले वर्ष 4.4 प्रतिशत की अपेक्षा अधिक है। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार भी मुद्रास्फीति के संबंध में चिन्तित है। सरकार ने राजकोषीय, मौद्रिक और आपूर्ति के संबंध में पहले ही अनेक उपाय कर लिए हैं जिससे कि कीमतों में स्थायित्व बना रहे और यदि जरूरत हुई तो वह और उपाय करने में नहीं हिचकेगी। जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, 2004 में सत्ता में आई थी, उस समय मुद्रास्फीति संबंधी ग्राफ बढ़ रहा था परन्तु हम मुद्रास्फीति कम करने से सफल रहे और हमें विश्वास है कि इस वर्तमान मुद्रास्फीति संबंधी प्रवृत्ति को भी कम कर सकेंगे।

II. भारत निर्माण और अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम

9. भारत निर्माण, सरकार की नीति का मूल आधार है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मौजूदा वित्त वर्ष में :

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन 900,000 हेक्टेयर सहित 2,400,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी।
- दिसम्बर, 2006 तक 55,512 आवासों को पेयजल उपलब्ध कराया गया जबकि लक्ष्य 73,120 आवासों का था;
- दिसम्बर, 2006 तक 12,198 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। आरआईडीएफ के अधीन अलग विंडों से कार्यक्रम के लिए एक वर्ष में निधियों में 4000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी।
- दिसम्बर, 2006 तक 783,000 ग्रामीण घरों का निर्माण कार्य किया गया है तथा 914,000 घरों का निर्माण कार्य चल रहा है और 1,500,000 घरों के निर्माण कार्य का वार्षिक लक्ष्य पार कर लिए जाने की संभावना है ;
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अब तक 19,758 गांवों को शामिल किया गया है ; और
- 20,000 गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के मुकाबले, 15,054 गांवों को टेलीफोन उपलब्ध कराए गए हैं, तथा शेष गावों को इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
- माननीय सदस्य यह देखेंगे कि भारत निर्माण प्रभावशाली रूप से आगे बढ़ता जा रहा है।

10. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के आठ अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी। इस समय, इन कार्यक्रमों का मैं कुछ विस्तारपूर्वक उल्लेख करना चाहूंगा।

III. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ

11. वर्ष 2007-08 से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ होगा। इसका घोषित लक्ष्य है–"त्वरित एवं अधिक समावेशी विकास"। मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूँ कि इस योजना की पूर्व संध्या पर अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है जो इसके पहले कभी नहीं रही। इसलिए हमारे लिए यह उचित हो जाता है कि उच्चतर लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह उल्लेख है कि इस "योजना का उद्देश्य निरंतर वृद्धि के पथ पर अर्थव्यवस्था का विकास करना है जिससे इस अवधि की समाप्ति पर लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हो सके"। इस योजना के अन्य उद्देश्यों में शामिल है : कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वृद्धि, तीव्रतर रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना और सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं सहित मूल भौतिक आधारभूत संरचना की सुलभता सुनिश्चित करना। मैंने विभिन्न क्षेत्रों को संसाधन आवंटित करते समय, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखा है।

सकल बजटीय सहायता

12. कुछ अड़चनों के होते हुए भी, मैं इस आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं। 2006-07 में सकल बजटीय सहायता 172,728 करोड़ रुपए नियत की गई थी और इसमें से केन्द्रीय आयोजना के लिए सहायता 131,284 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2007-08 के लिए सकल बजटीय सहायता बढ़ाकर 205,100 करोड़ रुपए की जाएगी। इसमें से केन्द्रीय आयोजना के लिए 154,939 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

मुख्य क्षेत्रों के लिए आवंटन

13. मैं भारत निर्माण के लिए, 2006-07 में 18,696 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) की तुलना में, 2007-08 में 24,603 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। यह 31.6 प्रतिशत अधिक है।

14. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र भी पर्याप्त निधियां प्राप्त करेंगे। मैं, वर्ष 2007-08 में शिक्षा के लिए आवंटन 34.2 प्रतिशत बढ़ाकर 32,352 करोड़ रुपए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 21.9 प्रतिशत बढ़ाकर 15,291 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना

15. संसाधनों के आवंटन में स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अत: मैं स्कूली शिक्षा के लिए, 2006 07 में किए गए 17,133 करोड़ रुपए के आबंटन में लगभग 35 प्रतिशत वृद्धि करके इसके लिए 2007-08 में 23,142 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं।

16. इस राशि में से, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को 10,671 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा, मैं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधान 162 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 450 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। अगले वर्ष हम 200,000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे और 500,000 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करेंगे।

17. मध्याह्न भोजन योजना के लिए अगले साल 7,324 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। हम वर्ष 2007-08 के आरम्भ में, प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को बढ़ाने के अलावा शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,427 प्रखंडों में उच्च प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव करते हैं।

18. प्रारंभिक शिक्षा कोष में अंतरण 8,746 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,393 करोड़ रुपए किया जाएगा।

19. जैसे-जैसे अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उन्हें माध्यमिक शिक्षा के लिए सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है। इस प्रयोजनार्थ योजनाएं बनाई जा रही हैं, और मैं माध्यमिक शिक्षा के लिए 2006-07 में किए गए 1,837 करोड़ रुपए के प्रावधान को दुगना कर 2007-08 में 3,794 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्तियां

20. यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान से स्कूलों में नामांकन दर में 96 प्रतिशत तक सुधार हुआ है, फिर भी स्कूल बीच में छोड़ने वालों का अनुपात अधिक बना हुआ है। कक्षा 8वी से 9वीं के बीच वाले वर्ष महत्वपूर्ण वर्ष प्रतीत होते हैं जब विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है। पढ़ाई बीच में छोड़ने के अनुपात को कम करने और विद्यार्थियों को कक्षा 8 के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से मैं एक राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। आठवीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को में से राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजित करके चयन किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को नवमी, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं में अध्ययन करने के लिए 6000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। मैं प्रतिवर्ष 100,000 छात्रवृत्तियां दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं। इस कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए, मैं इस वर्ष, 750 करोड़ रुपए की निधि सृजित करने तथा अगले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष इतनी ही राशि कार्पस में और देने का प्रस्ताव करता हूं। तदनुसार भारतीय स्टेट बैंक को 750 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा इस निधि से होने वाली आय का उपयोग छात्रवृत्तियां देने के लिए किया जाएगा।

पेय जल और स्वच्छता

21. राजीव गांधी पेय जल मिशन के अंतर्गत दिसम्बर, 2006 तक 55,512 आवासों तथा 34000 स्कूलों को पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। अब तक इस मिशन में शामिल न की गई अथवा छूट गई बस्तियों दोनों के लिए 2007-08 हेतु अधिक महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मैं इस मिशन के वास्ते 2006-07 में किए गए 4,680 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर 2007-08 में 5,850 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

22. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के संबंध में, मैं इस वर्ष किए गए 720 करोड़ रुपए के प्रावधान को, बढ़ाकर अगले वर्ष 954 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं।

स्वास्थ्य क्षेत्र; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

23. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) अपने कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष अपनी समय-सीमा के अनुसार कार्य कर रहा है। जिला और निचले स्तरों पर सभी स्वास्थ्य योजनाओं के सांस्थानिक एकीकरण का कार्य कर लिया गया है। देश में सभी जिले मार्च, 2007 तक

जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाएं बनाने का कार्य पूरा कर लेंगे। माता और बच्चे की परिचर्या तथा क्षय रोग और मलेरिया जैसी संचारी बीमारियों के निवारण एवं उपचार पर मुख्य रूप से बल दिया जाएगा। आंगनवाड़ी केन्द्रों में आयोजित मासिक स्वास्थ्य दिवसों (एमएचडी) के माध्यम से टीकाकरण, प्रसव के बाद देख-रेख तथा पोषाहार एवं स्वच्छता जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के बीच ताल-मेल रखा जाना है।

24. मुझे यह सूचित करते हुए, प्रसन्नता हो रही है कि 320,000 सहयोगी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एसएचए) की भरती की गई है और 200,000 से अधिक ने अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अलावा, राज्यों द्वारा 90,000 संपर्क कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षित एएसएचए को लगाए जाने से, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देख-रेख में पर्याप्त सुधार होगा। आयुर्वेद योग और प्राकृति चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी पद्धतियों (आयुष) को भी सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रदायक प्रणाली की मुख्य धारा में लाया जा रहा है। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 2006-07 में किए गए 8,207 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 2007-08 में 9,947 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

एचआईवी/एड्स

25. सरकार ने एचआईवी/एड्स की गोपनीयता को समाप्त किया है और इस बीमारी को शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य प्राप्त करने के साहसिक एवं दृढ़ निश्चयी प्रयास करने का वादा किया है। यदि इस बीमारी की व्यापकता दर, जनसंख्या के 1 प्रतिशत से कम है तो इस बीमारी को नियंत्रित समझा जाएगा। 2007-08 में शुरू हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी-3) तथा एनएसीपी-1 और एनएसीपी-2 के निर्माण के लक्ष्य सभी राज्यों में उच्च जोखिमों वाले समूह होंगे। हम कन्डोम की सुलभता बढ़ाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी के लिए रक्त जांच और सुरक्षित रक्त की उपलब्धता हो। ज्यादा अस्पतालों में एचआईवी/एड्स के इलाज की व्यवस्था होगी जिससे यह बीमारी मां से बच्चे को न लग पाए। भारतीय डाक्टरों द्वारा विकसित तथा 2006 में शुरू की गई बाल चिकित्सा खुराक संबंधी प्रोटोकॉल के लिए, सहायता दी जाएगी। मैं, वर्ष 2007-08 के लिए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रावधान बढ़ाकर 969 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

पोलियो

26. मैंने पिछले वर्ष यह आशा प्रकट की थी कि दिसम्बर, 2007 तक देश से पोलियों को खत्म कर दिया जाएगा। तथापि, 2006 के शुरू में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पोलियो फैलने की घटना हुई थी। पोलियो उन्मूलन की कार्यनीति को संशोधित किया गया है। पोलियो वैक्सीन देने के अभियानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, मोनोवॉलेन्ट वैक्सीन शुरू किया जाएगा तथा उत्तर प्रदेश के 20 तथा बिहार के 10 उच्च जोखिम वाले जिलों को सघन कवरेज दिया जाएगा। कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में एकीकृत कर दिया गया है। एएसएचए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए प्रत्येक बच्चे का पता लगाएंगे। मैं, पोलियो के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2007-08 में 1,290 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

27. एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के विस्तार के द्वितीय चरण में सरकार ने 173 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं, 107,274 आंगवाड़ी केन्द्रों और 25,961 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की मंजूरी दी है। ग्यारहवीं योजना के दौरान सभी बस्तियों और अधिवासों को इसमें शामिल करने और इसे गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए सरकार इस योजना के विस्तार के लिए वचनबद्ध है। मैं, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के निमित वर्ष 2006-07 में आवंटित 4,087 करोड़ रुपए को बढ़ाकर वर्ष 2007-08 में 4,761 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

28. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) 2 फरवरी, 2006 को आरम्भ की गई थी। इसके क्रियान्वयन की गति अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मांग उत्प्रेरित योजना है, इसमें रोजगार की कानूनी गारंटी निहित है, अत: बजट आवंटन को आवश्यकता के अनुसार सम्पूरित करना होगा। अत: मैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए (एनईआर संघटक सहित) 12,000 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार वर्तमान 200 जिलों से 330 जिलों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैंने इस स्कीम के अंतर्गत शामिल न किए गए जिलों में ग्रामीण रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हेतु 2,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

29. स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) का लक्ष्य स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के बीच स्व-रोजगार का विकास करना है। मैं, वर्तमान वर्ष के 1,200 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर अगले वर्ष में 1,800 करोड़ रुपए (एनईआर संघटक सहित) करते हुए इस कार्यक्रम को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करता हूं।

शहरी बेरोजगारी

30. शहरी बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन का मुद्दा समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए आवंटन 2006-07 में 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष 344 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

31. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को राज्य सरकारों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। आज की तारीख तक कई

राज्यों के अनेक शहरों में जलापूर्ति, स्वच्छता, परिवहन, सड़क और आवास जैसे क्षेत्रकों में 23,950 करोड़ रुपए की कुल लागत से 538 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मैं यह आवंटन 2006-07 में 4,595 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 4,987 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना

32. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अधीन और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों को अपरिवर्तित रखा गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यांकन मानीटरिंग, प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण के लिए एक आयोजना स्कीम 2007-08 में कार्यान्वित की जाएगी और इसमें पीडीएस का कम्प्यूटरीकरण और भारतीय खाद्य निगम में एक समेकित सूचना प्रणाली शामिल होगी।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

33. वर्ष 2005-06 में शुरू की गई परंपरा को जारी रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की योजनाओं संबंधी अलग विवरण बजट दस्तावेजों में रखे गए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2007-08 में आवंटन काफी बढ़ाया गया है। केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के संबंध में मैंने आवंटन बढ़ाकर 3,271 करोड़ रुपए कर दिया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कम से कम 20 प्रतिशत लाभ की योजनाओं के संबंध में मैंने आवंटन बढ़ाकर 17,691 करोड़ रुपए कर दिया है।

34. एम.फिल और पी.एचडी. में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी जाती है। मैं, इस कार्यक्रम के लिए आबंटन 2006-07 में 35 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 88 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

35. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। मैं इन छात्रवृत्तियों के लिए 2006-07 के 440 करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 2007-08 में 611 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए ऐसी ही छात्रवृत्ति हेतु 91 करोड़ रुपए के एक अलग प्रावधान का भी प्रस्ताव करता हूं।

अल्पसंख्यक

36. पिछले वर्ष मैंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की इक्विटी में 16.47 करोड़ रुपए का एक छोटा सा अंशदान किया था। सच्चर समिति की रिपोर्ट के बाद एनएमडीएफसी को अपने दायरे का विस्तार करना होगा और अपने प्रयत्नों में तेजी लानी होगी। अत: मैं एनएमडीएफसी की शेयर पूंजी में और 63 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

37. अनेक जिले अल्पसंख्यकों की अधिक आबादी वाले हैं। मैं इन जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए 108 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं।

38. अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए तीन छात्रवृत्ति कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मैं निम्नलिखित आबंटन करने का प्रस्ताव करता हूं :

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	–	72 करोड़ रुपए
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	–	90 करोड़ रुपए
स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर योग्यता-सह-सुविधा छात्रवृत्तियां	–	48.60 करोड़ रुपए

महिलाएं

39. बजटीय आबंटनों में महिलाओं के हितों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। 50 मंत्रालयों/विभागों ने जेंडर बजट निर्धारण कक्षों की स्थापना की है। वर्ष 2007-08 के लिए 27 मंत्रालयों/विभागों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में 33 अनुदान मांगों को बजट दस्तावेजों में प्रस्तुत एक विवरण में शामिल किया गया है। शत-प्रतिशत महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 8,795 करोड़ रुपए है और कम से कम 30 प्रतिशत महिला विशिष्ट कार्यक्रमों की स्कीमों के लिए 22,382 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। पिछले वर्ष के विवरण में जो त्रुटियां बताई गई थीं उन्हें दूर करने का हमने ईमानदारी से प्रयत्न किया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)

40. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आबंटनों से लिया गया कुल बजट आबंटन 2007-08 में बढ़ा दिया गया है जो 2006-07 में 12,041 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 14,365 करोड़ रुपए किया गया है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) को दिए गए 1,380 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति को उचित राजकोषीय प्रोत्साहनों के साथ 31 मार्च, 2007 से पहले तैयार कर लिया जाएगा।

सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) की अनुपूर्ति

41. अभी तक मैंने उन आबंटनों का जिक्र किया है जिनके अंतर्गत योजना "क" शामिल है और जिसका संसाधन बास्केट 205,100 करोड़ रुपए का है। योजना आयोग के परामर्श से मैंने योजना "ख" भी तैयार की है। चूंकि ग्यारहवीं योजना 1 अप्रैल, 2007 से शुरू होगी अत: हम इस बात को समझते हैं कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई पहल करने की आवश्यकता होगी। प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने और व्यय शुरू होने पर अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। अत: मैं वर्ष के दौरान बेहतर कर प्रशासन के जरिए 7,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करूंगा। योजना आयोग ने मुझे सलाह दी है कि यह अतिरिक्त निधियां इस सदन द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, शहरी आधार संरचना और जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में बांट दी जाएंगी।

42. मेरे पास योजना "ग" भी है। योजना "ग" के अंतर्गत, मैं बजट से बाहर उपलब्ध संसाधनों को काम में लाने और निवेश के प्रयोजन के लिए, विशेषकर आधारभूत संरचना क्षेत्र में, इन्हें बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं इस विषय पर थोड़ी देर में चर्चा करूंगा।

IV. कृषि

43. अब मैं हमारी मुख्य चुनौती कृषि पर चर्चा करूंगा। मुझे जवाहरलाल नेहरु के वे शब्द याद आते हैं जब उन्होंने कहा था "प्रत्येक अन्य इंतजार कर सकता है परन्तु कृषि नहीं"।

44. राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय कृषक नीति का मसौदा विचाराधीन है। इसी बीच कृषि की आर्थिक क्षमता सुधारने और उनकी न्यूनतम निवल आय सुनिश्चित करने के लिए मेरे पास अनेक प्रस्ताव हैं।

कृषि-ऋण

45. कृषि-ऋण संतोषजनक गति से बढ़ता जा रहा है। कृषि-ऋण तीन वर्ष में दुगना करने का लक्ष्य दो वर्षों में प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारित 175,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य आराम से पार हो जाएगा और इसके 190,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशा है। इस वर्ष दिसम्बर, 2006 तक, 53.37 लाख नए किसानों को सांस्थानिक ऋण प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2007-08 के लिए, मैं कृषि ऋण के रूप में 225,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित करने और 50 लाख नए किसानों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं।

46. अल्पकालिक फसल ऋणों के लिए दो प्रतिशत ब्याज सहायता स्कीम 2007-08 में जारी रहेगी और मैं इस प्रयोजन के लिए 1,677 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूं।

47. देश के चार राज्यों के 31 विशेष रूप से संकटग्रस्त जिलों में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें कुल 16,979 करोड़ रुपए की धनराशि निहित है। इसमें से लगभग 12,400 करोड़ रुपए जल संबंधी कार्यक्रमों के लिए हैं। किसानों को अनुपूरक आय प्रदान करने के लिए, विशेष योजना में अधिक दूध देने वाले पशुओं के संवर्धन और संबंधित क्रियाकलापों की एक स्कीम शामिल है। मैं इस योजना के लिए 153 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

कृषि-ऋणग्रस्तता

48. सरकार ने ऋणग्रस्तता के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए डा. आर. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने संपूर्ण देश में व्यापक रूप से परामर्श किए हैं और वह अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।

दाल-मिशन

49. सरकार दालों का उत्पादन और उत्पादकता न बढ़ने के प्रति चिंतित है। एक बड़ी कमी प्रमाणित बीजों की उपलब्धता और गुणवत्ता की है। अत: मैं एकीकृत तिलहनों, पाम ऑयल, दाल और मक्का विकास कार्यक्रम के विस्तार का प्रस्ताव करता हूं। प्रजनक, मूल और प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बीज निगमों, कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर केन्द्रों, कृभको, इफको और नाफेड तथा बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों को बीजों का उत्पादन बढ़ाने हेतु योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सरकार आईआईपीआर, कानपुर के विस्तार का निधिपोषण करेगी और तीन वर्ष की अवधि में प्रमाणित बीजों का उत्पादन दुगुना करने के लिए अन्य उत्पादकों को पूंजी अनुदान या रियायती वित्तपोषण प्रदान करेगी।

बागान क्षेत्र

50. चाय पौध पुन: लगाने और उसे बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रयोजनी चाय निधि शुरू की गई है । सरकार कॉफी, रबर, मसालों, काजू और नारियल के लिए इसी प्रकार की वित्तीय कार्यप्रणाली शीघ्र स्थापित करेगी ।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

51. शीघ्रतम संभावित समय में अधिक सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) का पुनर्सुदृढ़ीकरण किया गया है । वर्ष 2006-07 में 35 परियोजनाओं के पूरा होने की आशा है और 900,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा । वर्ष 2006-07 में 7,121 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में, 2007-08 के लिए परिव्यय बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपए किया जाएगा । इसमें से राज्य सरकारों के लिए अनुदान का हिस्सा 3,580 करोड़ रुपए होगा, जो 2,350 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ा दिया गया है ।

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम

52. जल संभरण विकास और भूमि उपयोग के अन्य पहलुओं से संबंधित सभी स्कीमों के समन्वय हेतु कुछ महीने पहले राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई । मैं नए वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव रखता हूं ।

जल संसाधन प्रबंधन : जल निकायों की बहाली

53. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मार्च, 2005 में जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली के लिए 13 राज्यों में एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी । मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि विश्व बैंक ने 400,000 हेक्टेयर के कमान क्षेत्र वाले 5,763 जल निकायों की बहाली हेतु तमिलनाडु के साथ 2,182 करोड़ रुपए के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं । आंध्र प्रदेश के लिए एक करार का निष्पादन मार्च, 2007 में किए जाने की आशा है और इसके अंतर्गत 250,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र के साथ 3,000 जल निकाय शामिल होंगे। कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए ऐसी ही परियोजनाएं तैयार करने का कार्य विभिन्न स्तरों पर है और जून, 2007 से पहले कम से कम दो और करार पूरे करने की आशा है । मैं अन्य राज्य सरकारों से प्रस्तावों के साथ आगे आने का आग्रह करता हूं ताकि अगले दो वर्षों में संपूर्ण देश को इसमें शामिल किया जा सके ।

भूमि जल पुनर्भरण

54. भूमिगत जल स्रोत का रिक्त होते जाना गंभीर स्तर पर पहुंच गया है । केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने देश में "अति उपयोग" या "संकटपूर्ण" के रूप में 1,065 आकलन ब्लाकों की पहचान की है । इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक ब्लाक सात राज्यों के 100 जिलों में हैं । भूमि जल पुनर्भरण की कार्य योजना वर्षा जल को "डग वैल" में परिवर्तित करने की है । प्रत्येक ढांचे की लागत लगभग 4,000 रुपए होगी । छोटे और मझोले किसानों की भूमि पर बने लगभग दो मिलियन कुओं सहित यह आवश्यकता सात मिलियन कुओं की है । मैं छोटे और मझोले किसानों के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी और अन्य किसानों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रस्ताव करता हूं । जल संसाधन मंत्रालय शीघ्र ही स्कीम को अंतिम रूप देगा । इस आशा में, नाबार्ड को 1,800 करोड़ रुपए की धनराशि अंतरित करने का मेरा इरादा है । इस धनराशि को निलंब में रखा जाएगा और लाभार्थियों को संबंधित जिले के अग्रणी बैंक के माध्यम से वितरित किया जाएगा ।

किसानों को प्रशिक्षण

55. थोड़े से शिक्षण और प्रशिक्षण से हमारे किसान अच्छी जल प्रबंधन पद्धतियों को आसानी से सीख लेंगे । अत: मैं प्रस्ताव रखता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) प्रत्येक 32 चुने गए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर संस्थानों में एक शिक्षण-सह-प्रदर्शन जल उपयोग मॉडल स्थापित करे । प्रत्येक संस्थान प्रतिवर्ष 100 प्रशिक्षकों और 1,000 किसानों को क्रमश: दो सप्ताह और एक सप्ताह के कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देगा । आवर्ती लागतों के अनुमानों के आधार पर, मेरा एक कार्पस निधि के सृजन के लिए प्रत्येक संस्था को 3 करोड़ रुपए का ब्याज रहित ऋण प्रदान करने का इरादा है । इस निधि से प्राप्त आय का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए किया जाएगा । कुल लागत 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

विस्तार प्रणाली

56. 1960 के दशक की हरित क्रांति हमारे हजारों कृषि विस्तार कर्मचारियों द्वारा लाई गई थी जिन्होंने प्रशिक्षण एवं दौरा (टी एंड वी) नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे किसानों के साथ कार्य किया । खेद है कि यह विस्तार प्रणाली निष्प्राण हो चुकी प्रतीत होती है । विस्तार कार्य को जीवित करने के लिए कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों के परामर्श से एक नया कार्यक्रम तैयार करेगा जो उचित परिवर्तन के साथ प्रशिक्षण एवं दौरा कार्यक्रम की अनुकृति तैयार करेगा ।

57. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी (एटीएमए), जो अब 262 जिलों में चल रही है, का विस्तार 2007-08 में अन्य 300 जिलों में किया जाएगा । मैं एटीएमए के लिए प्रावधान 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष 230 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं ।

उर्वरक सब्सिडी

58. मैंने 2006-07 में उर्वरक सब्सिडियों के लिए 17,253 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की थी। संशोधित अनुमानों के अनुसार यह बढ़कर 22,453 करोड़ रुपए हो जाएगी और अधिक धन की मांग है । जहां उर्वरकों को वास्तव में सब्सिडी दी जानी चाहिए वहां हमें सीधे ही किसानों को सब्सिडी देने की वैकल्पिक पद्धति का पता लगाना चाहिए । उर्वरक उद्योग इस संबंध में उर्वरक विभाग के साथ अध्ययन करने और समाधान ढूंढने के लिए सहमत है । इस रिपोर्ट के आधार पर, सरकार का इरादा 2007-08 में प्रत्येक राज्य के कम से कम एक जिले में पायलट कार्यक्रम कार्यान्वित करने का है ।

कृषि बीमा

59. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) अपने वर्तमान रूप में वर्ष 2007-08 की खरीफ और रबी के लिए जारी रहेगी । मैं इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूं ।

60. कृषि बीमा निगम (एआईसी) खरीफ, 2004 से एक पायलट मौसम बीमा योजना चलाता आ रहा है और यह जोखिम कम करने की एक अधिक आशाजनक योजना प्रतीत होती है । अतः सरकार एनएआईएस के विकल्प के रूप में संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से दो या तीन राज्यों में पायलट आधार पर मौसम आधारित एक बीमा योजना शुरू करने के लिए एआईसी से कहेगी । इस योजना को सब्सिडी के साथ बीमांकिक आधार पर संचालित किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए मेरा इरादा 2007-08 में 100 करोड़ रुपए आबंटित करने का है ।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

61. नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है । कृषि ऋणों की मात्रा बढ़ने और ग्रामीण ऋण सहकारिता सुधार संबंधी वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से पुनर्वित्त की मांग बढ़ेगी । इसके संसाधन बढ़ाने के लिए मैं 5,000 करोड़ रुपए तक के ग्रामीण बांड जारी करने की नाबार्ड को स्वीकृति देने का प्रस्ताव रखता हूं । इन बांडों पर सरकारी गारंटी दी जाएगी और यह उचित कर छूट के योग्य होंगे।

ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि

62. ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) राज्य सरकारों को निधियों की स्वीकृति और वितरण करती है । वर्ष 2006-07 में नाबार्ड ने 10,000 करोड़ रुपए के कार्पस में से अभी तक 8,440 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की हैं और यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा । इन निधियों के लिए बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए मैं 2007-08 में आरआईडीएफ-XIII के कार्पस को बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं । मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि वह इन निधियों का, मुख्यतः राज्य के संकटग्रस्त जिलों में उपयोग करें ।

63. आरआईडीएफ के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 4,000 करोड़ रुपए की धनराशि से एक अलग विंडो खोली गई थी । इसमें से 2006-07 के लिए 2,311 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं । मैं 2007-08 में आरआईडीएफ-XIII के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए के कार्पस के साथ अलग विंडो जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं ।

सामाजिक सुरक्षा

64. राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में की गई एक वचनबद्धता यह थी कि सरकार असंगठित कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी । डा. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिस पर विचार किया जा रहा है । निर्णय लिए जाने तक असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की चिंता को प्रदर्शित करते हुए मैं एक शुरुआत करने का प्रस्ताव रखता हूं । "आम आदमी बीमा योजना" (एएबीवाई) नामक एक नई योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से मृत्यु एवं विकलांगता बीमा कवर के विस्तार का मैं प्रस्ताव करता हूं । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) की रिपोर्ट संख्या 491 के अनुसार ऐसे परिवारों की अनुमानित संख्या लगभग 1.5 करोड़ है । मार्च, 2007 के अंत तक 70 लाख परिवार कुछ राज्य सरकारों और एलआईसी की सामाजिक सुरक्षा निधि की सहायता से एलआईसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शामिल कर लिए जाएंगे । एएबीवाई के अंतर्गत मैं ऐसे ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं जिन्हें अभी तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है और यह संख्या उससे अधिक हो सकती है जिसका उल्लेख एनएसएस की रिपोर्ट में किया गया है । परिवार के मुखिया या परिवार के एक कमाऊ सदस्य का बीमा किया जाएगा । केन्द्र सरकार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 200 रुपए की किस्त का 50 प्रतिशत वहन करेगी और मैं, राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वह लाभार्थियों की ओर से शेष 50 प्रतिशत वहन करने के लिए आगे आएं । केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाने वाली वार्षिक लागत को ध्यान में रखते हुए, मैं, एक निधि में 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि रखने का प्रस्ताव करता हूं जिसकी देखभाल एलआईसी द्वारा की जाएगी । मैं राज्य सरकारों के परामर्श से इस स्कीम को अंतिम रूप से तैयार करने और 2007-08 में इसका कार्यान्वयन शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं ।

65. अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी 15 मिनट या इससे अधिक समय, कृषि की चर्चा पर लिया है। योजनाओं की कोई कमी नहीं है, निधियों की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमारा इरादा है उसे पूरा किया जाए। संत तिरुवल्लूवर हमें देख रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं :–

"उड़विनर कई मडंगिन इल्लइ विड्इवधूम विट्टमे इम्बरकुम निलइ
(यदि किसान हाथ पर हाथ धर कर बैठे हों तो संसार का त्याग करने वाले संतों को भी मोक्ष नहीं मिल सकता)"

V. निवेश

66. सभी संकेतक अर्थव्यवस्था में निवेश दर में तेजी को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिये, सकल घरेलू पूंजी गठन (जीडीसीएफ) में 2005–06 में, पिछले वर्ष से 23.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बढ़कर 11,47,254 करोड़ रुपए हो गया। मेरा विश्वास है कि यह प्रवृत्ति 2006–07 में जारी है। अप्रैल-जनवरी, 2006–07 में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 12.5 बिलियन अमरीकी डालर था जिसने पोर्टफोलियो निवेश को भी पीछे छोड़ दिया जो 6.8 बिलियन अमरीकी डालर था।

67. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई), आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के माध्यम से, 2007–08 में 165,053 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। सरकार सीपीएसई को 16,361 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता और 2,970 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करेगी।

68. इसके अलावा, मौजूदा वर्ष में, हमने आठ सीपीएसई को 1,590 करोड़ रुपए नकद प्रदान कर और 1,612 करोड़ रुपए की नकद भिन्न सुविधाएं देकर उनका पुनर्गठन किया है।

VI. आधारभूत संरचना

विद्युत

69. विद्युत उत्पादन ने इस वर्ष अप्रैल-दिसम्बर की अवधि में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की है। फिर भी, दसवीं योजना की समाप्ति पर, हम पांच वर्ष की अवधि में केवल 23,163 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त कर पायेंगे जिसमें 2004-2005 से शुरू हुए तीन वर्षों में प्राप्त की गयी 16,339 मेगावाट की क्षमता भी शामिल है। अत: यह अनिवार्य है कि हम नये उपाय करें।

70. विद्युत मंत्रालय ने शासन और मुन्द्रा में दो अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) का निष्पादन किया है। सात और ऐसी परियोजनाओं पर कार्रवाई चल रही है और हमें भरोसा है कि कम से कम दो का निष्पादन जुलाई, 2007 तक शुरू हो जाएगा। विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई अन्य पहलों में शामिल हैं–प्रावेट डेवलपर्स द्वारा मर्चेन्ट पावर प्लांट्स की स्थापना की सहायता और पारेषण परियोजनाओं में निजी भागीदारी।

71. इसके अलावा, त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार परियोजना (एपीडीआरपी) ने 213 नगरों में संपूर्ण तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीसी) नुकसानों को काफी कम किया है। 50,000 से अधिक की आबादी वाले सभी जिला मुख्यालयों और नगरों को शामिल करने के लिए एपीडीआरपी का पुनर्गठन किया जा रहा है। मैं एपीडीआरपी के लिये बजटीय सहायता, 2006–07 में 650 करोड़ रुपए की तुलना में अगले वर्ष बढ़ाकर 800 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

72. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के कार्यान्वयन की गति और वार्षिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मैं इसका आवंटन 2006–07 में 3,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007–08 में 3,983 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

कोयला

73. पिछले वर्ष की घोषणा के बाद, 8,581 मिलियन टन के आरक्षित भंडारों के 26 कोयला ब्लाकों और 755 मिलियन टन आरक्षित भंडारों वाले चार लिग्नाइट ब्लाकों को दिसम्बर, 2006 तक सरकारी कंपनियों और अनुमोदित अंतिम प्रयोक्ताओं को आवंटित किया गया है। विनिर्दिष्ट अन्तिम उपयोग की परिभाषा का विस्तार किया जाएगा ताकि उसमें भूमिगत कोयले से गैस बनने और कोयला द्रवीकरण को शामिल किया जा सके।

राष्ट्रीय राजमार्ग

74. स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का कार्य लगभग समाप्ति पर है और उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम मार्ग परियोजना में काफी अधिक प्रगति हुई है। इसके 2009 तक पूरा होने की सम्भावना है।

एनएचडीपी-III, एनएचडीपी-V और एनएचडीपी-VI, की आयोजना अथवा कार्यान्वयन की दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है । अब तक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने व्यवहार्यता अन्तर निधिपोषण के रूप में 2,072 करोड़ रुपए दिए हैं, परन्तु इसे ऋणात्मक अनुदान के रूप में 1,900 करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अधीन बढ़ाया गया निजी क्षेत्र का निवेश 25,366 करोड़ रुपए हैं । उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) के अधीन, 2006-07 में 450 किलोमीटर के निर्माण का काम दिया जा चुका है और शेष कार्य 2007-08 में दिया जाएगा । मैं आगामी वर्ष में राजमार्ग विकास प्राधिकरण के लिए प्रावधान 2006-07 में 9,945 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,667 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं ।

75. मुंगेर बिहार में गंगा पर सड़क-सह-रेल पुल का निर्माण कार्य एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इसी तरह बोगीबील, असम में ब्रह्मपुत्र पर सड़क-सह-रेल पुल का निर्माण कार्य एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा ।

सरकारी निजी भागीदारी और व्यवहार्यता अंतर निधिपोषण

76. सरकारी निजी भागीदारी मॉडल से आधारभूत ढांचे के निर्माण और रख-रखाव में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी लाई जा सकी है । अब तक व्यवहार्यता अंतर निधिपोषण योजना के अधीन 37 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 21 प्रस्तावों को 'सिद्धांतत:' मंजूरी दी जा चुकी है जिसकी कुल परियोजना लागत 9,842 करोड़ रुपए है और इसमें 2,521 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यवहार्यता अंतर निधिपोषण है । गति धीमी है और बैंक ग्राह्य परियोजनाओं का सूचीपत्र तैयार करने के लिए अधिक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए पेश किया जा सके । क्षमता निर्माण और परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए पहले उठाए गए कदमों के अतिरिक्त परियोजना तैयार करने में शीघ्रता लाने के लिए मेरा 100 करोड़ रुपए की मूल निधि (कार्पस) से एक परिक्रमी निधि की स्थापना करने का इरादा है । इस निधि से ब्याज रहित ऋण के रूप में, जिसे अंतत: सफल निविदाकार से वसूल किया जाएगा, आरम्भिक व्यय के 75 प्रतिशत तक का अंशदान किया जाएगा । निधि को प्रचालित करने संबंधी दिशा निर्देशों की घोषणा यथासमय की जाएगी ।

VII. उद्योग

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

77. उर्जा सुरक्षा, सरकार की कार्यसूची में उच्च प्राथमिकता पर है । नई खोज लाइसेंसिंग नीति के छह दौरों में अब तक 162 उत्पादन भागीदारी संविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं । भारतीय और विदेशी कंपनियों ने पहले ही खोज कार्य के लिए 97,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है । इसी प्रकार नीलामी बोली के तीन दौरों के बाद खोज के लिए 23 कोयला बेड मिथेन ब्लाकों की संविदा दी जा चुकी है ।

वस्त्र

78. पुन: सुदृढ़ीकृत वस्त्र उद्योग वैश्विक चुनौती का सामना करने को तत्पर है । एकीकृत वस्त्रोद्योग पार्कों की योजना के अधीन स्वीकृत 30 पार्कों में से अब तक 26 पार्कों को मंजूरी दी जा चुकी है । मैं इन पार्कों के लिए 2006-07 में किये गए 189 करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 2007-08 में 425 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं ।

79. मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टी.यू.एफ.) योजना ग्यारहवीं योजना अवधि में जारी रखी जाएगी । 2006-07 में 535 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में 2007-08 में 911 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का मैं प्रस्ताव करता हूं । पहले की तरह, हथकरघा क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा ।

हथकरघा

80. हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए 2005-06 में एक समूहन (क्लस्टर) नीति आरम्भ की गई थी अ[illegible]20 समूहों का चयन किया गया है । वर्तमान वर्ष में 273 नए धागा डिपो खोले गए हैं और हथकरघा मार्क आरम्भ किया गया । सरकार का 200[illegible]08 में 100-150 अतिरिक्त समूहों को जिम्मे लेने का प्रस्ताव है । अब कार्यान्वित की जा रही 12 स्कीमों को ग्यारहवीं योजना अवधि में पांच स्क[illegible] में संमूहीकृत किया जाएगा । स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 300,000 बुनकरों को लाया गया है और इसके अंतर्गत और अधिक बुनक[illegible] को लाया जाएगा। इस योजना में अनुषंगी कामगारों को शामिल करने के लिए भी इसका विस्तार किया जाएगा। मैं इस सेक्टर के लिए 200[illegible]07 में आवंटित 241 करोड़ रुपए की धनराशि बढ़ाकर अगले वर्ष 321 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं ।

लघु और मझोले उद्यम

81. लघु और मझोले उद्यमों (एसएमई) के लिए अगस्त 2005 में घोषित ऋण नीति के बाद, इस क्षेत्र के लिए बकाया ऋण दिसम्बर 2005 के अंत में 135,200 करोड़ रुपए से बढ़कर दिसम्बर 2006 के अंत में 173,460 करोड़ रुपए हो गया । बैंकों को इन उद्यमों के लिए और अधिक ऋण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, मेरा बैंकों से ब्याज दर का निर्धारण करते समय किसी लघु और मझोले उद्यम द्वारा हासिल क्रेडिट रेटिंग को ध्यान में रखने के लिए कहने का प्रस्ताव है ।

नारियल जटा उद्योग

82. नारियल जटा एक पारिस्थितिकी अनुकूल फाइबर है । नारियल जटा उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है तथा इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है । मुझे नारियल जटा उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक स्कीम की

घोषणा करते हुए प्रसन्नता है जिसमें प्रमुख नारियल जटा उत्पादक राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा पर विशेष जोर दिया जाएगा । मैं 22.50 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं ।

VIII. सेवा क्षेत्रक

विदेश व्यापार

83. हमारे पण्य निर्यातों ने 2005-06 में 100 बिलियन अमरीकी डालर के उच्च स्तर को पार किया और वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक इसके 125 बिलियन अमरीकी डालर की ऊंचाई को छूने की आशा है । विदेश व्यापार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के दुगने से अधिक की दर से बढ़ रहा है । सरकार निर्यात-अनुकूल नीतियों का अनुसरण करना जारी रखेगी ।

पर्यटन

84. मेरा प्रस्ताव पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए प्रावधान 2006-07 में 423 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 520 करोड़ रुपए करने का है ।

IX. वित्तीय क्षेत्रक

बैंकिंग

85. संसद के समक्ष महत्वपूर्ण वैधानिक उपायों के अलावा सरकार का बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में अनेक पहलें करने का प्रस्ताव है ।

86. सरकार, भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की इक्विटी धारिता प्राप्त करने का प्रस्ताव करती है । मैंने इस प्रयोजनार्थ 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है परन्तु इस लेनदेन से सरकार को कोई घाटा नहीं होगा ।

87. विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) स्कीम, लाभप्रद व्यवसायों में लगे समाज के कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत की दर पर वित्त उपलब्ध कराती है । मेरा प्रति लाभार्थी ऋण की सीमा 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने और आवासीय ऋण की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

88. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण ऋण के वितरण में तीसरी शक्ति के रूप में उभरे हैं और प्रायोजक बैंकों ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये बैंक और अधिक जिम्मेदारियां लेने के इच्छुक हैं । डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित वित्तीय समावेशन संबंधी समिति ने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं । अतः मेरा प्रस्ताव है कि :

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक आक्रामक शाखा विस्तार कार्यक्रम शुरू करने और 2007-08 में देश के कवर न किए गए 80 जिलों में कम से कम एक शाखा खोलने के लिए कहा जाए ;
- वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा ब्याज प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम का विस्तार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर किया जाए;
- इन बैंकों को एनआरई/एफसीएनआर जमा राशियां स्वीकार करने की अनुमति दी जाए; और
- उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जिनकी निवल संपत्ति ऋणात्मक है, को एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पुनः पूंजी प्रदान की जाए ।

आवास ऋण

89. राष्ट्रीय आवास बैंक शीघ्र ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नूतन योजना 'प्रतिवर्ती बंधक' आरम्भ करेगा जिसके अंतर्गत एक वरिष्ठ नागरिक जो किसी मकान का स्वामी है, अपने मकान को बंधक रखने के एवज में निश्चित मासिक आय प्राप्त कर सकता है, जबकि वह ऋण की अदायगी या शोधन किए बिना अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में मकान का स्वामी बना रहेगा और उस पर काबिज रहेगा ।

90. हमारे लोग आवास ऋण चाहते हैं । बैंक और आवास वित्त कंपनियां जो बंधक रखने के बदले ऋण देती हैं, के लिए अधिक सुविधाजनक होगा यदि बंधकनामे को उधारकर्ता, ऋणदाता और गारंटीदाता के बीच एक त्रिपक्षीय संविदा के जरिए गारंटी प्रदान की जाए । बंधक गारंटी कंपनियों के गठन को अनुमति देने वाले विनियम लाए जाएंगे ।

बीमा

91. राष्ट्रपति जी ने नेशनल इंश्योरेंश कम्पनी द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अनन्य स्वास्थ्य बीमा योजना का 6 दिसम्बर, 2006 को उद्घाटन किया । मैंने अन्य तीन सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसी प्रकार की योजनाओं की पेशकश करने को कहा है और उन्होंने 2007-08 में ऐसा करने पर सहमति प्रकट की है ।

92. लघु वित्तीय क्षेत्रक (विकास और विनियमन) विधेयक तथा बीमा कानूनों में संशोधन के लिए एक व्यापक विधेयक बजट सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे ।

वित्तीय समावेशन

93. वित्तीय समावेशन समाज के कमजोर तबकों की वहनीय लागत पर समय पर और पर्याप्त ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है । वित्तीय समावेशन संबंधी समिति ने एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है । जहां हम अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हैं, वहीं सरकार ने तत्काल इसकी दो सिफारिशें कार्यान्वित करने का फैसला किया है । पहली सिफारिश विकासात्मक और संवर्धनात्मक उपायों की लागत वहन करने हेतु नाबार्ड में एक वित्तीय समावेशन निधि की स्थापना करना है । दूसरा प्रौद्योगिकी अपनाने की लागतों को पूरा करने के लिए एक वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थापना करना है । प्रत्येक निधि में 500 करोड़ रुपए का एक समग्र कार्पस होगा और इसका आरम्भिक निधिपोषण केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा किया जाएगा ।

पूंजी बाजार

94. पूंजी बाजार वित्तीय संशाधनों में मध्यस्थता करने का महत्वपूर्ण माध्यम है । भारतीय पूंजी बाजार की सुदृढ़ता को मान्यता देते हुए इंटरनेशनल आर्गेनाजेशंस ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन्स ने अपना वार्षिक सम्मेलन अप्रैल, 2007 में मुम्बई में आयोजित करने का निर्णय लिया है । बाजार को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिवर्ष घोषित उपायों की श्रृंखला में, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :-

- प्रतिभूति बाजार के सभी भागीदारों के लिए पैन को एकमात्र पहचान संख्या बनाया जाए जिसमें किसी विशेष प्रकार के खाता में अन्तर करने के लिए एक अल्फा न्यूमेरिक उपसर्ग या प्रत्यय हो;
- विभिन्न बाजार भागीदारों के लिए सेबी द्वारा बनाये जाने वाले विनियमों के अधीन स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की विचारणा को आगे बढ़ाना और यदि आवश्यक हो तो एक समर्थकारी कानून द्वारा समर्थित किया जाएगा ।
- म्युचुअल फंडों को विनियुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर निधियां शुरू करने और प्रचालित करने की अनुमति देकर आधारभूत ढांचा क्षेत्र को निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना;
- व्यक्तियों को भारतीय म्युचुअल फंडों के माध्यम से निवेश करने की अनुमति देकर व्यक्तियों और भारतीय म्युचुअल फंडों को विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देने वाले विभिन्न विनियमों को एकस्थ करना ;
- संस्थाओं द्वारा डिलीवरी को सुविधाजनक बनाने के लिए डिलीवरी द्वारा परिनिर्धारित अल्पकालिक बिक्री और प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने की अनुमति देना;
- भारतीय कंपनियों को उनकी वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनिमेय बांडों के निर्गम द्वारा ग्रुप कंपनियों में उनकी धारिताओं के हिस्से को बेचने की अनुमति देने के लिए एक समर्थकारी व्यवस्था कायम करना ।

आधारभूत संरचना के लिए अभिनव वित्तपोषण

95. राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से राज्यों की उधार लेने की न्यूनतम बाध्यता को कम करके निवल संग्रहण के 80 प्रतिशत पर लाया गया है । केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पिछले एनएसएसएफ ऋणों की वापसी अदायगी भी 2005-06 से शुरू हो चुकी है । जिससे दीर्घकालिक उधारों के लिये संसाधन उपलब्ध होंगे । अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये निधियां भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) द्वारा एनएसएसएफ से भी उधार ली जा सकती हैं ।

96. एक सार्थक पहल, सिटीग्रुप, ब्लैकस्टोन, आईडीएफसी और आईआईएफसीएल द्वारा 5 बिलियन अमरीकी डालर के आधारभूत ढांचा वित्तपोषण अभिक्रम की शुरूआत है ।

97. आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए श्री दीपक पारेख की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने अनेक सिफारिशें की है। उनमें से एक सिफारिश मौद्रिक विस्तार का जोखिम उठाए बिना विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का एक छोटा भाग इस्तेमाल करने के बारे में है । समिति ने आईआईएफसीएल की दो पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी अनुषंगी कंपनियों की स्थापना की सिफारिश की है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

(i) भारतीय रिजर्व बैंक से निधियां उधार लेना और भारत में आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही भारतीय कंपनियों को उधार देना; अथवा ऐसी परियोजनाओं के लिए उनकी विदेशी वाणिज्यिक उधारों को पूर्णत: से भारत के बाहर पूंजीगत व्यय के लिए वित्तपोषित करना; और

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से निधियां उधार लेना, ऐसी निधियों को उच्च दर वाली संपर्श्विक प्रतिभूतियों में निवेशित करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में संसाधनों को जुटाने हेतु भारत में आधारभूत संरचना की परियोजनाओं को ''ऋण कवच'' बीमा उपलब्ध कराना ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन दो अनुषंगी कंपनियों को दिए जाने वाले ऋणों को भारत सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक अपने वृद्धिशील निवेश पर प्रतिफल की औसत दर की अपेक्षा अधिक प्रतिफल के प्रति आश्वस्त होगा । सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श कर सिफारिश के विधिक और विनियामक पक्षों की जांच करने का प्रस्ताव है ताकि आधारभूत संरचना के लिए वित्तीय संसाधन बढ़ाने की अभिनव पद्धति का पता लगाया जा सके ।

X. अन्य प्रस्ताव

रक्षा व्यय

98. मैं रक्षा के लिए आवंटन बढ़ाकर 96,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं । इसमें 41,922 करोड़ रुपए पूंजी परिव्यय के लिए होगा । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सुरक्षा के लिए किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किया जाएगा ।

सूचना प्रौद्योगिकी

99. सरकार ने ई-गवर्नेंस हेतु एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में दक्षता, सुविधा, पहुंच तथा पारदर्शिता मे सुधार करना है और सरकार की सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है । मैं ई-गवर्नेंस हेतु आवंटन को 2006-07 में 395 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 719 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं । केन्द्र सरकार ई-गवर्नेंस कार्य योजना को राज्य स्तरों पर सहायता देती है और मैं ऐसी सहायता हेतू आवंटन में वर्ष 2006-07 में 300 करोड़ रुपए से बढोतरी कर 2007-08 में 500 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं । मैं सॉफ्टवेयर निर्यात उद्योग हेतु मानव शक्ति विकास की एक नई योजना के लिए 33 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव करता हूं ।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

100. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि ने वर्ष 2006-07 में 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए । मैं वर्ष 2007-08 में इस आवंटन को बढ़ाकर 5,800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं । यह दो संघटकों का वित्त पोषण करेगा, पहला, 250 जिलों से संबंधित होगा और दूसरे का बिहार के विशेष आयोजना से संबंध होगा । उड़ीसा के केबीके जिले जिन्हे 250 जिलों में शामिल किया गया है, सहायता की वही राशि प्राप्त करते रहेंगे जो विगत में प्राप्त करते रहे हैं ।

वित्तीय केन्द्र के रूप में मुम्बई

101. मुम्बई को एक क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्र बनाने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने हाल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । मेरा इरादा इस रिपोर्ट को लोगों की सामान्य जानकारी में लाना और उनकी प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करना है । मुझे आशा है कि हम समिति की मुख्य सिफारिशों पर सर्वसम्मति बनाने और मुम्बई में विश्वश्रेणी के वित्तीय केन्द्र को प्रोत्साहन देने तथा 'वित्तीय सेवाओं' को भारत का अगला विकास इंजन बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे ।

व्यावसायिक शिक्षा मिशन

102. आर्थिक विकास के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हमारे पास कुशल तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति का भंडार हो । कई क्षेत्रों मे पहले ही इसका अभाव हो गया है । इसके अलावा, हम कामकाजी आयु की जनसंख्या में बढ़ोतरी द्वारा जनसांख्यिकी लाभांश का फायदा तभी उठा सकते हैं जब हमारे युवकों और युवतियों में अपेक्षित दक्षता हो । प्रधान मंत्री ने 2006 के अपने स्वतंत्रता दिवस के सम्बोधन में व्यावसायिक शिक्षा मिशन की बात की थी । योजना आयोग में एक कार्यदल व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में कार्ययेजना को तैयार कर रहा है । वैकल्पिक मॉडल को अपनाया जा सकता है परन्तु यह दृष्टिकोण सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित होगा । मैं इस मिशन का कार्य प्रारम्भ करने हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रारम्भिक प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं ।

आईटीआई का उन्नयन

103. माननीय सदस्यों को याद होगा कि सरकार ने वर्ष 2005 से पांच वर्षों में 500 आईटीआई के उन्नयन का कार्यक्रम चलाया था । उन्नयन किए गए पहले चरण के 100 आईटीआई में अगस्त, 2005 से उन्नयन किए गए दूसरे चरण के 100 आईटीआई में अगस्त, 2006 से संशोधित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए । मुझे आशा है कि अन्य 300 आईटीआई को अगस्त, 2009 तक कवर कर लिया जाएगा । उसके बाद भी 1,396 सरकारी आईटीआई बचे रहेंगे ।

104. मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत विशिष्ट व्यवसायों तथा कौशल के उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में 1,396 आईटीआई का उन्नयन किया जाए । प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, आईटीआई के स्वामित्व के रूप में राज्य सरकार, प्रवेश तथा शुल्कों को विनियमित करती रहेगी ; नए प्रबन्धन को शैक्षणिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाएगी और केन्द्र सरकार प्रारम्भिक धन के जरिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी । आईटीआई को दूसरी शिफ्ट प्रारम्भ करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा । एक बार तीनों हिस्सेदारों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने पर मैं प्रत्येक आईटीआई के उन्नयन तथा पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं । मैं वर्ष 2007-08 से शुरू करके प्रत्येक वर्ष सरकारी निजी भागीदारी के तहत कम से कम 300 आईटीआई के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं । मैंने इस उद्देश्य हेतु 750 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है ।

विकलांगों के लिए रोजगार

105. समाज के लाभवंचित वर्गों में विकलांग व्यक्ति शामिल हैं । वे नियमित रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं । संगठित क्षेत्रक में नियोक्ताओं को नियमित रोजगार उपलब्ध करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु, मैं एक ऐसी योजना का प्रस्ताव करता हूं जिसके अंतर्गत एक बार विकलांग व्यक्ति को नियमित करने पर और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के अंतर्गत नामांकित करने पर सरकार नियोक्ता को पुरस्कृत करेगी । इस योजना के अंतर्गत सरकार पहले तीन वर्षों के लिए नियोक्ता के ईपीएफ तथा ईएसआई में किए गए अंशदान की प्रतिपूर्ति करेगी । सरकार विकलांग व्यक्तियों हेतु 25,000 रुपए प्रतिमाह की वेतन सीमा वाले लगभग 100,000 रोजगारों के सृजन को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है । मेरा अनुमान है कि जब यह योजना पूर्णत: अस्तित्व में आ जाएगी तो सरकार पर प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा जो बढ़कर प्रतिशत 450 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा । इसलिए मैंने इसके लिए 1,800 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं ।

ऋण प्रबंधन कार्यालय

106. सम्पूर्ण विश्व में ऋण प्रबन्धन मौद्रिक प्रबंधन से भिन्न है । सरकार के अधीन ऋण प्रबन्धन कार्यालय (डीएमओ) की स्थापना की काफी समय से वकालत की जाती रही है । अब तक प्राप्त राजकोषीय समेकन ने हमें पहला कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित किया है । तद्नुसार मैं एक स्वशासी ऋण प्रबन्धन कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ और पहले चरण में एक मध्यवर्ती कार्यालय की स्थापना की जाएगी जो पूर्णतः डीएमओ के साथ लेन-देन को सुविधाजनक बनाएगा ।

विकास सहयोग

107. अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के बढ़ते रुतवे के अनुरूप हमें स्वेच्छा से अन्य विकासशील देशों के विकास के संवर्धन में अधिक उत्तरदायित्व लेना होगा । वर्तमान में भारत कई मंत्रालयों और एजेंसियों के माध्यम से विकास सहयोग देता है और इसकी कुल राशि लगभग 1 बिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष है । यह अनुभव किया गया है कि विकास सहयोग संबंधी सभी गतिविधियों को एक छत्र के नीचे लाया जाए । तदनुसार सरकार भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (ईडका) की स्थापना का प्रस्ताव करती है । विदेश, वित्त और वाणिज्य मंत्रालय और अन्य भागीदारों को ईडका में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ।

जलवायु परिवर्तन

108. भारत का ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में न तो कोई महत्वपूर्ण योगदान है और न ही निकट भविष्य में वह ऐसा करेगा । तो भी, ''साझा परन्तु विशिष्ट उत्तरदायित्व'' के सिद्धांत के अनुरूप भारत ने ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन प्रभाव के अनुकूल बनने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं । भारत ने क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र का भी संदृढ़ उन्नयन किया है और इसके पास विश्व की सबसे अधिक स्वच्छ विकास की परियोजनाएं हैं । फिर भी, भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील देशों में से है । अतः, सरकार, भारत पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्यन करने और भविष्य में हमारे द्वारा किए जाने वाले उपायों की पहचान हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है ।

राष्ट्रमंडल खेल

109. भारत ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 दिल्ली में कराने का दावा रखा और इसमें सफलता प्राप्त की । राष्ट्र ने बड़ा गौरव महसूस किया जब भी राजीव गांधी के मार्गदर्शन में हमने 1982 में सफलतापूर्वक एशियाई खेलों का आयोजन किया । हम इसका सारा श्रेय अपने देशवासियों को देते हैं कि वे इन राष्ट्रमंडल खेलों को भी उतनी ही यादगार घटना बनाएं । मैं 2007-2008 में इन खेलों के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय को 150 करोड़ और दिल्ली सरकार को 350 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव करता हूँ । इसी तरह, मैं पुणे में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेल 2008 के लिए 50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ ।

इतिहास और संस्कृति

110. चूंकि हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का 150वां वर्ष और सत्याग्रह आंदोलन का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं । ऐसे हमारा ध्यान उन संस्थाओं की ओर जाता है जो गांधी जी के कार्य और अन्य रचनात्मक कार्य कर रहे हैं । मैं उन चार संस्थाओं, जिनके कार्यों के प्रति हम कृतज्ञ हैं, के लिए 30 करोड़ रुपए अलग रखने की इच्छा व्यक्त करता हूँ । ये चार संस्थायें साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, भंडारकर ओरियंटल अनुसंधान संस्थान, पुणे, और राजेंद्र स्मृति संग्रहालय, पटना हैं । मेरा इरादा बौद्धिक कार्यकलाप के एक प्रमुख केंद्र होने के नाते नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्कालय, दिल्ली की संग्रह क्षमता के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था करने का भी है ।

111. संस्कृति मंत्रालय ने विशिष्ट परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए भारतीय और विदेशी संस्थाओं में शिक्षाविदों को रखने का प्रस्ताव किया है । उनकी नियुक्ति की शर्तें शिक्षाविदों को स्वतंत्रता और नम्यता उपलब्ध कराएंगी । मैं इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ रुपए का आरंभिक अनुदान देने का इरादा रखता हूँ ।

उत्कृष्ट संस्थाएं

112. मैं विगत दो वर्षों की तरह उत्कृष्टता को महत्व देने के लिए को 100 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान देने का प्रस्ताव करता हूँ । सरकार ने गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर और तामिलनाडू, कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबतूर का चयन किया है और प्रत्येक को 50 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी ।

XI लोक वित्त

113. राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों की बदौलत केंद्र सरकार और राज्य राकारों ने अपना खोया हुआ राजकोषीय आधार पुनः प्राप्त कर लिया है । राज्यों के ऋण के 110,268 करोड़ रुपए समेकित किए जा चुके हैं । बीस राज्यों ने 8,575 करोड़ रुपए की ऋण माफी का लाभ उठाया है ।

114. वर्ष 2006-07 में केंद्र, राज्यों को करों और शुल्कों में उनके हिस्से के रूप में 120,377 करोड़ रुपए देगा । वर्ष 2007-08 में यह राशि बढ़कर 142,450 करोड़ रुपए हो जाएगी । इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना और आयोजना-भिन्न दोनों के अंतर्गत कुल अनुदान और ऋण 2006-07 में 90,521 करोड़ रुपए से बढ़कर 2007-08 में 106,987 करोड़ रुपए हो जाएंगे ।

वैट, सीएसटी और जीएसटी की रुपरेखा

115. मूल्य वर्धित कर (वैट) सम्पूर्ण सफल सिद्ध हुआ है । इसे क्रियान्वित करने वाले राज्यों का वैट राजस्व 2005-2006 में 13.8 प्रतिशत और 2006-07 के पहले नौ महीनों में 24.3 प्रतिशत बढ़ा है । अगला तर्कसंगत उपाय केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को चरणबद्ध रुप से समाप्त करना है । मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि सीएसटी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ एक सहमति पर पहुंच गई है । इसके परिणामस्वरूप, सीससटी दर 1 अप्रैल, 2007 से 4 प्रतिशत से घटा कर 3 प्रतिशत कर दी जाएगी । मैंने वैट और सीएसटी के कारण हानियां यदि काई होती हैं, की प्रतिपूर्ति के लिए 5,495 करोड़ रुपए की व्यस्था की है ।

116. मैं राज्य सरकारों और विशेष रूप से उनके वित्त मंत्रियों द्वारा प्रदर्शित सहकारी संघवाद की भावना की तहेदिल से प्रशंसा करना चाहता हूँ । मेरे अनुरोध पर, राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति 1 अप्रैल, 2010 से राष्ट्रीय स्तर के सामान और सेवा कर (जीएसटी) शुरू करने हेतु एक रुपरेखा बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य करने को सहमत हो गई है ।

117. जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के अनुसार आगे बढ़ रहा है । संशोधित अनुमान के आधार पर मुझे यह सूचित करते हुए खुशी है कि चालू वर्ष का राजस्व घाटा 2.0 प्रतिशत (2.1 प्रतिशत के बजट अनुमान की तुलना में) और राजकोषीय घाटा 3.7 प्रतिशत (3.8 प्रतिशत के बजट अनुमान की तुलना में) होगा ।

XII वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान

118. अब मैं 2007-08 के बजट अनुमानों की ओर आता हूँ ।

आयोजना व्यय

119. मेरा अनुमान है कि 2007-08 में 205,100 करोड़ रुपए का आयोजना व्यय होगा । कुल व्यय के अनुपात के रूप में (भारतीय स्टेट बैंक के शेयर अधिग्रहण को घटाकर) आयोजना व्यय 32.0 प्रतिशत होगा ।

आयोजना-भिन्न व्यय

120. वर्ष 2007-208 में आयोजना-भिन्न व्यय (भारतीय स्टेट बैंक के शेयर अधिग्रहण को घटाकर) 435,421 करोड़ रुपए अनुमानित है । वर्ष 2006-07 की तुलना में वृद्धि सिर्फ 6.5 प्रतिशत है ।

राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा

121. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान में कुल 680,521 करोड़ रुपए (भारतीय स्टेट बैंक के शेयर अधिग्रहण हेतु 40,000 करोड़ रुपए सहित) अनुमानित हे । केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 486,422 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय 557,900 करोड़ रुपए अनुमानित है । इसके परिणामस्वरूप, 71,478 करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुमानित है जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत है । राजकोषीय घाटा 150,948 करोड़ रुपए अनुमानित है जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है । मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर हैं ।

भाग-ख

XIII कर प्रस्ताव

122. अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ ।

123. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने वायदा किया था कि "कर दरें स्थिर और वृद्धि, अनुपालन एवं निवेश में सहायक" होंगी । सकल कर राजस्व में वृद्धि निभाए गए वचन का प्रमाण है । यद्यपि, हमने अधिक कर राजस्व जुटाया है, हमने बचत के रूप में और निवेश के लिए अपने लोगों के हाथों में अधिक धन भी छोड़ा है ।

124. इस सरकार के पहले तीन सालों में सकल कर राजस्व 19.9 प्रतिशत 20.0 प्रतिशत और 27.8 प्रतिशत बढ़ा है । जीडीपी-कर अनुपात 2003-04 में 9.2% से बढ़कर 2006-07 में 11.4% हो गया । हमारा इरादा कर दरों को संतुलित और स्थिर रखना है और कर कानूनों का संचालन करदाता-अनुकूल तरीके से करना है ।

अप्रत्यक्ष कर

125. मैं अप्रत्यक्ष करों से शुरू करता हूँ । पहले, सीमा शुल्क ।

126. सरकार ने जनवरी, 2007 में टैरीफ में अनेक कटौतियां घोषित की हैं । पूंजीगत माल, परियोजना आयात, धातुओं और विनिर्दिष्ट अकार्बनिक रसायनों पर आयात शुल्क 2.5 प्रतिशतांक तक और कुछ मामलों में 5 प्रतिशतांक तक घटाए गए थे । कुछ खाद्य तेलों पर शुल्क 10 से 12.5 प्रतिशतांक कम किया गया था ।

127. पूर्वी एशियाई तुलनीय दरों की तरफ एक कदम और बढ़ाने के लिए, मैं कृषि-भिन्न उत्पादों के लिए शीर्ष दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ ।

128. मैं अधिकतर रसायनों और प्लास्टिक पर शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ ।

129. उत्कृष्ट इस्पात पर शुल्क 5 प्रतिशत है । घटिया और खराब इस्पांत आपूर्ति सुदृढ़ करते हैं । विभेदक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं घटिया और खराब इस्पात पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ ।

130. मैं राख तत्व को ध्यान में रखे बगैर सभी प्रकार के कोकिंग कोयले को पूर्णतया शुल्क मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

131. पिछले साल, मैंने सभी मानव-निर्मित रेशों और धागों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया था। इस उद्योग को और प्रोत्साहित करने के लिए मैं पालिएस्टर रेशे और धागे पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। परिणामस्वरूप, डीएमटी, पीटीए और एमईजी जैसे कच्चे माल पर भी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया जाएगा।

132. रत्न और आभूषण अभिवृद्धि और रोजगार का अन्य चालक उद्योग है। मैं कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों पर शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत; खुरदरे कृत्रिम नगों पर शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत; और अनगढ़ मूंगों पर शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

133. मैं तलकर्षकों को पूर्णतया आयात शुल्क से मुक्त करता हूँ।

134. सिंचाई सुविधाएं मजबूत करने और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु मैं ड्रिप सिंचाई प्रणालियों, कृषि फव्वारों और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी पर शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

135. जबकि विनिर्दिष्ट चिकित्सा उपस्करों पर 5 प्रतिशत का रियायती शुल्क लगता है, अन्य उपस्करों पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगता है। मैं चिकित्सा उपस्करों पर आयात शुल्क की सामान्य दर कम करके 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

136. खाद्य तेलों को और सस्ता करने के लिए मैं कच्चे तेल और परिष्कृत खाद्य तेलों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त सीवी शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूं। मैं सूरजमूखी के तेल, कच्चे और परिष्कृत दोनों पर शुल्क 15 प्रतिशतांक घटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

137. मेरे पास कुत्ते और बिल्ली प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार है। मैं पालतू जीवों के भोजन पर शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

138. मैं घड़ियों के डायलों और स्पन्दन तथा छातों के पार्ट्स पर शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

139. अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए मैं सहकारी निधिपोषित अनुसंधान संस्थाओं को उपलब्ध 5 प्रतिशत रियायती दर का शुल्क वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान निदेशालय में पंजीकृत सभी अनुसंधान संस्थाओं को देने का प्रस्ताव करता हूँ। भेषजीय और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के लिए मैं 15 विनिर्दिष्ट मशीनरी पर शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

140. सरकार और अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा, हेलीकाप्टरों सहित वायुयानों का आयात वर्तमान में सभी शुल्कों से मुक्त है और यह स्थिति जारी रहेगी। तथापि, अन्य निजी आयातकों को इस छूट की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, मैं हेलीकाप्टरों सहित वायुयानों के सभी निजी आयातों पर 3 प्रतिशत आयात शुल्क, जो डब्ल्यूटीओ निर्धारित दर है, लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसे आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क भी लगेगा।

141. होंडा समिति ने खनिज नीति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसरण में और अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा तथा राजस्व जुटाने के लिए, मेरा लौह अयस्क और सान्द्रों के निर्यात पर 300 रुपए प्रति मीट्रिक टन और क्रोम अयस्क तथा सान्द्रो के निर्यात पर 2,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन का निर्यात शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।

142. मैं अब अपने उत्पाद शुल्कों तथा सेवा कर सम्बन्धी प्रस्तावों की ओर आता हूँ।

143. सामान्य सेनवेट दर अथवा सर्विस कर दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

144. सरकार ने 15 फरवरी, 2007 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश: 2 रुपए प्रति लीटर तथा 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। मैं सहमत हूँ कि इस बोझ का एक भाग राजस्व पर पड़ेगा। इसलिए, मेरा प्रस्ताव है कि पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क के यथामूल्य संघटक को 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया जाए।

145. समाज के विभिन्न तबकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, मेरा प्रस्ताव न्यायसंगत मामलों में विशेष रूप से रोजगार सृजक क्षेत्रों में उत्पाद शुल्क से राहत प्रदान करने का है।

- मैं लघु उद्योग के लिए छूट सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उच्च विकास प्राप्त करने को कटिबद्ध है। पिछले वर्ष कई खाद्य मदों में रियायतें प्रदान की गयी थीं। मैं इस वर्ष ऐसे बिस्कुटों पद उत्पाद शुल्क की पूर्ण छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ जिनका खुदरा बिक्री मूल्य 50 रु. प्रति किग्रा. से ज्यादा न हो। साथ ही मैं सभी प्रकार के खाद्य मिश्रणों जिसमें तत्काल तैयार होने वाले मिश्रण भी शामिल हैं, को उत्पाद शुल्क से पूर्णत: छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। अब मुझ पर इडली और डोसा मिश्रण के प्रति पक्षपात करने का आरोप नहीं लगेगा।
- मैं छातों तथा जूतों की सहायक सामग्रियों में उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।
- प्लाईवुड से काष्ठ बचत में मदद मिलती है। अत: मैं प्लाईवुड पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।
- बायोडीजल हमारी जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता काफी हद तक घटाएगा। इसलिए मैं बायोडीजल को उत्पाद शुल्क से पूर्णत: छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

146. प्रत्येक घर तथा समुदायों में खाद्य पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, मैं जल के शुद्धिकरण की ऐसी युक्तियों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं जो विनिर्दिष्ट झिल्ली आधारित प्रौद्योगिकियों तथा बिजली का उपयोग न करने वाले घरेलू वाटर फिल्टर से संचालित हों ।

147. जलापूर्ति संयंत्र से भण्डारण सुविधा में उपयोग में आने वाले जल पाइपों को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है । मैं यह छूट सीमा जल आपूर्ति प्रणालियों में उपयोग में आने वाले 200 मिलीमीटर से अधिक व्यास के सभी पाइपों को भी देने का प्रस्ताव करता हूँ ।

148. सीमेंट के थोक मूल्यों में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है । पिछले वर्ष, इस समय 50 किग्रा. सीमेंट का बैग 190 रुपए अथवा उससे कम के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर बेचा जा रहा था जिसे मैं लाभकारी मूल्य मानता हूँ । मैं एक ओर कीमतों की सीमा में रहने वाले सीमेंट विनिर्माताओं को पुरस्कार देने और दूसरी ओर इस सीमा से बाहर जाने वाले विनिर्माताओं पर कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ । तद्नुसार, मैं ऐसे सीमेंट पर 400 रुपए प्रति मीट्रिक टन की उत्पाद शुल्क की मौजूदा दर को 350 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव करता हूँ जो खुदरा में 190 रुपए प्रति बैग से अधिक की दर पर नहीं बेचा जा रहा है । जिस सीमेंट की एमआरपी अधिक है, उस पर उत्पाद शुल्क 600 रुपए प्रति मीट्रिक टन होगा ।

149. मैं, ''तम्बाकू सेवन न करें'' अभियान का भी पुरजोर समर्थन करता हूं । इसलिए मैं सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दरों को लगभग 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं । इसी प्रकार, बीड़ी पर उत्पाद शुल्क (उपकर को छोड़कर) जिसे वर्ष 2001 में निर्धारित किया गया था, को मशीन से न बनी हुई बीड़ियों के सम्बन्ध में प्रति हजार 7 रुपए से बढ़ाकर 11 रुपए और मशीन निर्मित बीड़ियों के लिए प्रति हजार 17 रुपए से बढ़ाकर 24 रुपए किया जाएगा । वर्ष में 20 लाख तक की ब्रांड रहित बीड़ियों के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क से छूट है । इस छूट के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इसलिए अब से यह छूट केन्द्रीय उत्पाद विभाग की घोषणा तथा नियमित मॉनिटरिंग की शर्त पूरा करने पर उपलब्ध होगी ।

150. तम्बाकू युक्त पान मसालों पर 66 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क जारी रहेगा । तथापि, तम्बाकू रहित पान मसाले के सम्बन्ध से यह शुल्क 66 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत किया जाएगा । मैं तम्बाकू युक्त पान मसाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के सम्बन्ध में प्रदान की जा रही छूट जो पूर्वोत्तर राज्यों की यूनिटों को दी जाती हैं, को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ ।

151. छूटों की व्यापक समीक्षा पर आधारित तथा उन्हें वेबसाइट पर डालने और उन पर टिप्पणियां आमंत्रित करने के पश्चात्, मैं उन कतिपय उत्पाद शुल्क छूटों को हटाने का प्रस्ताव करता हूँ जो अनावश्यक है अथवा अपनी उपयोगिता खो चुके हैं ।

152. मैं छोटे सेवा-प्रदायकों के लिए छूट की सीमा को 400,000 रुपए से बढ़ाकर 800,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ । परिणामस्वरूप, कुल 400,000 निर्धारितियों में से 200,000 निर्धारिती सेवा कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे । इससे 800 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि मैं इस धनराशि को छोटे सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ता के हित में छोड़ रहा हूँ ।

153. जहां एक ओर मुझे 200,000 निर्धारितियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, वहीं दूसरी ओर मैं कर दायरे में आने वाले नए निर्धारितियों का स्वागत करता हूँ । मैं निम्नलिखित के सम्बन्ध में सेवा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ :

- खनिज, तेल अथवा गैस के खनन हेतु बाहर से आयातित सेवाएं;
- वाणिज्य अथवा व्यवसाय के उपयोग में आने वाली अचल सम्पत्ति को किराए पर देना, तथापि, आवासीय सम्पत्तियों, कृषि तथा इसके सदृश उद्देश्यों हेतु उपयोग में आने वाली खाली पड़ी भूमि, खेलकूद, मनोरंजन तथा पार्किंग उद्देश्य हेतु काम में आने वाली भूमि आर शैक्षणिक अथवा धार्मिक प्रयोजनों के लिए अचल संपत्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा;
- टेलीकॉम तथा विज्ञापन उद्देश्यों हेतु उपयोग में आने वाली वस्तुओं का विकास तथा आपूर्ति;
- वैयक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी परिसम्पत्ति प्रबन्धन सेवाएं; और
- डिजाइन सेवाएं ।

154. राज्य सरकार निर्माण कार्यों की संविदा के निष्पादन में लगे सामान में सम्पत्ति के अन्तरण पर कर लगाती है । निर्माण कार्यों की संविदा में सेवाओं के मूल्य पर सेवा कर लगना चाहिए, इसलिए, मैं निर्माण कार्यों की संविदा में लगे सेवाओं पर सेवा-कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ । परन्तु मैं एक वैकल्पिक संघटक योजना का भी प्रस्ताव करता हूँ जिसके तहत सेवा-कर निर्माण कार्यों की संविदा के कुल मूल्य के केवल 2 प्रतिशत पर ही लगाया जाएगा ।

155. मैं रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों द्वारा अपने सदस्यों को, जो प्रदत्त सेवाओं के सम्बन्ध में प्रतिमाह, 3000 रुपए अथवा उससे कम का योगदान करते हैं, उपलब्ध कराई गयी सेवाओं पर सेवा-कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ ।

156. अभिनव प्रोत्साहन हेतु, मैं प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूवेटर्स द्वारा उपलब्ध कराई गयी सभी सेवाओं पर सेवा कर से छूट का प्रस्ताव करता हूँ । इसी प्रकार, 50 लाख तक के वार्षिक कारोबार करने वाले इन्क्यूवेटी को पहले तीन वर्षों में सेवा-कर से छूट प्राप्त होगी ।

157. भारत को औषध परीक्षण के सम्बन्ध में एक वरीय गंतव्य स्थल बनाने हेतु, मैं नई औषधियों के नैदानिक परीक्षण को सेवा कर से छूट प्रदान करता हूं।

158. कुछ सेवाओं का दायरा जिन पर वर्तमान में कर लगाया जाता है, उसे विस्तारित अथवा पुनर्परिभाषित किया जा रहा है, तथापि, मैं विस्तार में जाकर सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा।

159. दूर संचार उद्योग ने बार-बार यह अनुरोध किया है कि उद्योग से सम्बन्धित अनेक करों, प्रभारों तथा शुल्क को एकीकृत किया जाए तथा एकल राजस्व शुल्क की वसूली की जाए। यह अनुरोध विचारणीय है। इसलिए, मैं दूर संचार विभाग से उद्ग्रहणों की मौजूदा संरचना के अध्ययन हेतु समिति का गठन करने और सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के अनुरोध का प्रस्ताव करता हूं।

प्रत्यक्ष कर

160. मैं अब प्रत्यक्ष करों की ओर आता हूं।

161. चालू वर्ष में, व्यष्टियों द्वारा बेहतर कर अनुपालन की प्रवृत्ति देखी गयी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी।

162. वैयक्तिक आय कर (पीआईटी) की चालू स्लैब और दरें केवल दो वर्ष पहले प्रारम्भ की गयी थीं। वे एक संतुलित कर प्रणाली का निर्माण करती हैं। प्रस्तावित आय कर कोड की एक व्यापक समीक्षा की जाएगी, जिसे इसी वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, दरों में कोई परिवर्तन किए बिना, मैं करदाताओं को विशेष रूप से उनके द्वारा राजस्व विभाग को दिए गए अपने सहयोग को देखते हुए कुछ राहत प्रदान करने पर विचार कर रहा हूं। तद्नुसार, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

- सभी निर्धारितियों के मामले में छूट की प्रारम्भिक सीमा को 10,000 रुपए बढ़ाया जाएगा, इस प्रकार प्रत्येक निर्धारिती को 1,000 रुपए की राहत प्राप्त होगी;
- परिणामस्वरूप, महिला निर्धारिती के मामले में प्रारम्भिक सीमा को 1,35,000 रुपए बढ़ाकर 1,45,000 रुपए किया जाएगा, इस प्रकार उन्हें 1,000 रुपए की राहत प्राप्त होगी;
- वरिष्ठ नागरिकों के मामले में छूट की प्रारम्भिक सीमा को 1,85,000 रुपए से बढ़ाकर 1,95,000 रुपए किया जाएगा, इस प्रकार उन्हें 2,000 रुपए की राहत प्राप्त होगी; और
- धारा 80घ के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में कटौती को अधिकतम 15,000 रुपए की सीमा तक बढ़ाया जाएगा, और वरिष्ठ नागरिकों के मामले में यह अधिकतम सीमा 20,000 रुपए होगी।

163. कम्पनी आय कर (सीआईटी) की दिशा में भी, अनुपालन अच्छा रहा है। परिणामस्वरूप, मैं सीआईटी में भी एक महत्वपूर्ण संशोधन के साथ वहीं दर रखने का प्रस्ताव करता हूं। लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ताकि उनमें निवेश हो और वे प्रगति करें, मैं सभी 1 करोड़ रुपए या उससे कम की कर योग्य आय वाली फर्मों और कम्पनियों पर आय कर पर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखता हूं। इससे लगभग 1,200,000 फर्म और कम्पनियां लाभान्वित होंगी।

164. प्राथमिक सोसायटियों और प्राइमरी बैंकों (अर्थात् पीएसी और पीसीए आर डीबी) को छोड़कर लाभ कमाने वाले सहकारी बैंकों को अन्य बैंकों के समान स्तर पर लाया गया है। तथापि, मेरे ध्यान में कुछ विसंगतियां भी आई हैं और सहकारी बैंकों के हित में मेरा उनमें सुधार लाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, धारा 36(1)(viii) का लाभ सहकारी बैंकों को उपलब्ध होगा। उसी प्रकार, सरकारी बैंकों को भी धारा 36(1)(vii क) के अंतर्गत अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान के संबंध में कटौती करने की अनुमति होगी। बैंकिंग कम्पनियों का समामेलन और विघटन (डिमर्जर) कर तटस्थ है और यह लाभ सहकारी बैंकों को भी प्रदान किया जाएगा।

165. आय कर अधिनियम की धारा 80झक उन आधारभूत सुविधाओं को सूचीबद्ध करती हैं जो कर रियायतों की हकदार हैं। इस लाभ के कुछ प्रत्यक्ष दावेदार हैं। पूरे देश में प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क, जिसमें गैस पाइप लाइन और इस नेटवर्क से एकीकृत भंडारण सुविधाएं शामिल हैं, इसका एक दावेदार है। दूसरा है, समुद्र में नौवहन तंत्र। मैं इन दोनों सुविधाओं को कर रियायत देने का प्रस्ताव करता हूं।

166. शहरी अवसंरचना के सृजन को सुसाध्य बनो की दृष्टि से मैं शहरी स्थानीय निकायों के एक समूह के लिए निधियां जुटाने हेतु बनाई गई स्टेट पूल्ड फाइनांस एंटीटीज के माध्यम से कर-मुक्त बांडों को जारी करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

167. पिछले वर्ष मैंने रत्न और आभूषण उद्योग के संबंध में कर नीति पर सरकार को सलाह देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इसकी सिफारिशों, श्रेष्ठतम अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालियों और एक सरल कर ढांचे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मैं हीरों के विनिर्माण और व्यापार में लगे उन निर्धारितियों के लिए जो ऐसे क्रियाकलापों से कारोबार के 8 प्रतिशत या अधिक मुनाफे की घोषणा करते हैं। एक सरल कराधान प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव करता हूं। इस संबंध में शीघ्र ही अनुदेश जारी किए जाएंगे।

168. हमें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 20,000 और अधिक होटल कमरों की आवश्यकता होगी। अतः मैं दो, तीन या चार सितारा होटलों के साथ-साथ उन सम्मेलन केन्द्रों के लिए भी जिनमें बैठने की क्षमता 3,000 से कम न हो, आय कर से पांच वर्ष का करावकाश देने का प्रस्ताव करता हूं। उन्हें 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2010 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली अथवा फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर से लगे जिलों में उन्हें बनाकर अपना कार्य प्रचालन आरम्भ कर देना चाहिए।

169. धारा 35 (2कख) में आंतरिक अनुसंधान और विकास से संबंधित व्यय के लिए 150 प्रतिशत की भारित कटौती की अनुमति है । मैं, 31 मार्च, 2012 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए यह रियायत बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं ।

170. वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में स्थित उपक्रम करावकाश प्राप्त कर रहे हैं जो 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाला है । उस राज्य में ओर निवेश को बढ़ाने के महत्व पर विचार करते हुए, मैं इस लाभ को 31 मार्च, 2012 तक और पांच वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं ।

171. इस वित्तीय वर्ष में आरम्भ की गई कम्पनियों की आय-विवरणियां इलैक्ट्रानिकी माध्यम से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सराहनीय सफलता जारी है । 31 जनवरी, 2007 तक, कम्पनियों द्वारा 301,736 आय विवरणियां इलैक्ट्रानिकी माध्यम से भरी गई हैं । हमारा विश्लेषण बताता है कि सभी कम्पनियों द्वारा कर की प्रभावी दर, जो केवल 19.2 प्रतिशत थी, का भुगतान किया गया है जिसके लिए अनेक कर रियायतों और छूटों को श्रेय जाता है--उनमें से अनेक नेक इरादे की थीं । वर्ष 1996-97 में हमने वही खाता लाभों वाली कम्पनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) लागू किया था जिसका प्रयोजन कराधान में लगभग अनुप्रस्थ समानता लाना है । अतः, जहां तक संभव हो सके, सभी कम्पनियों की आय पर मैट (एमएटी) लागू होना चाहिए । इसलिए, मैं उन कम्पनियों की आय पर मैट (एमएटी) लागू करने का प्रस्ताव करता हूं जिन्होंने आय कर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अंतर्गत कटौती का दावा किया है ।

172. मैं आंशिक रूप से एक ऐसी कटौती को संशोधित करने का प्रस्ताव रखता हूं जो कतिपय कम्पनियों को उपलब्ध है । आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत निवल मूल्य के दुगुने के बराबर विशेष प्रारक्षित राशियों की समग्र सीमा को बदले बगैर मैं प्रत्येक वर्ष लाभ की 20 प्रतिशत कटौती तक सीमित करते हुए अवधि को बढ़ाने और लाभों को बैंकों तथा कतिपय वित्तीय निगमों तक सीमित रखने का प्रस्ताव करता हूं ।

173. उद्यम पूंजी निधियां, विशेष रूप से ज्ञान-आधारित क्षेत्रों में उद्यम आरम्भ करते हेतु जोखिम पूंजी का एक उपयोगी साधन है क्योंकि ऐसी निधियां माध्यम स्तर (पास थ्रु स्टेट) की होती हैं, इसलिए वास्तविक वांछनीय क्षेत्रों में किए गए निवेशों के संबंध में कर लाभों को सीमित करना आवश्यक है । तदनुसार, मैं जैव-प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और साफ्टवेयर विकास से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी, नैनोटेक्नोलाजी, बीज अनुसंधान एवं विकास, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नए रसायन तत्वों का अनुसंधान एवं विकास, डेयरी उद्योग, कुक्कुट उद्योग और जैविक-ईंधनों के उत्पादन में उद्यम पूंजी वाले उपक्रमों में केवल निवेशों के संबंध में उद्यम पूंजी निधियों को माध्यम स्तर (पास थ्रु स्टेट) देने का प्रस्ताव रखता हूं । पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भी मैं उन उद्यम पूंजी निधियों को यह लाभ उठाने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता हूं जो कतिपय किस्म और आकार के होटल-सह-सम्मेलन केंद्रों में निवेश करते हैं ।

174. दिसम्बर, 2006 में मैंने आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग के अन्तर्गत एनएचएआई और आरईसी द्वारा जारी किए गए पूंजी लाभ बांडों के संबंध में प्रतिवर्ष प्रति-निवेशक 50 लाख रुपए की सीमा रखी थी । इसके परिणामस्परूप, अनेक लघु-निवेशकों ने इन बांडों को प्राप्त करके पूंजी लाभों पर बचत भी की है । मैं इस प्रावधान को जारी रखने का प्रस्ताव करते हुए तद्नुसार इस आशय की धारा 54ङ ग को संशोधित करने का प्रस्ताव रखता हूं ।

175. मैं कला के कतिपय कार्यों को शामिल करने के लिए पूंजी लाभों के कराधार को बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं ।

176. मेरा विश्वास है कि मेरे प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव और अधिक समस्तरीय समानता लाये हैं । विषमस्तरीय समानता को सुधाराना भी अनिवार्य है । भुगतान की क्षमता पर ध्यान देते हुए कम्पनियों द्वारा संवितरित लाभांशों पर लाभांश संवितरण कर की दर को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ।

177. मुद्रा बाजार म्यूच्युअल फंडों और लिक्विड म्यूच्युअल फंडों द्वारा संवितरित लाभांशों को रियायती कर दरों का लाभ मिलता है जिससे बड़ी मात्रा में विवाचन के अवसर बढ़ते हैं । मैं ऐसी ईकाइयों द्वारा प्रदत्त लाभांशों पर लाभांश संवितरण कर को सभी निवेशकों के लिए 25 प्रतिशत करके इस विकृति को दूर करने का प्रस्ताव रखता हूं ।

178. अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) अब स्थिर हो गया है । मुझे बिक्री संवर्धन के कुछ पहलुओं के संबंध में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । अतः मैं, निःशुल्क नमूनों पर व्यय के साथ-साथ प्रदर्शनों पर व्यय को एफबीटी की परिसीमा से निकालते हुए संदेहों को स्पष्ट करने का प्रस्ताव करता हूं ।

179. अनेक कम्पनियां कर्मचारी स्टाक आप्शन प्लान (ईएसओपी) के माध्यम से कर्मचारियों को अनुषंगी लाभ प्रदान करती हैं । मैं ईएसओपी को एफबीटी के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव कराता हूं । अनुषंगी लाभ कर निर्धारण मूल्य विकल्प को कार्यान्वित करने की तारीख से एक निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाएगा ।

180. बैंकिंग नकदी लेनदेन कर (बीसीटीटी) बेहिसाबी धन को पकड़ने और उसके स्रोत तथा गन्तव्य स्थान का पता लगाने का एक अत्यन्त उपयोगी साधन बना हुआ है । इससे आय कर विभाग को अनेक प्रकार से काले धन को उपयोग में लाने और हवाला लेनदेनों का पता लगा है । प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नकदी आहरणों को बीसीटीटी के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव करता हूं । इसके अतिरिक्त, मैं व्यक्तियों और अविभाजित हिन्दु परिवारों के लिए इस छूट की सीमा को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं । चूंकि अन्य साधन भी अत्यधिक प्रभावी हो चुके हैं, अतः मैं समझता हूं कि बीसीटीटी की पुनरीक्षा अगले वर्ष करना संभव होगा ।

181. मेरा शिक्षा के लिए उपकर के संबंध में प्रस्ताव है । जहां बुनियादी शिक्षा के निधिकरण हेतु सभी करों पर 2 प्रतिशत का उपकर बना रहेगा, वहां माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा और सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु 54 प्रतिशत क्षमता विस्तार करने के लिये निधियां जुटाने की क्षमता विस्तार हेतु सभी करों पर 1 प्रतिशत का अतिरिक्त उपकर लगाने का मेरा प्रस्ताव है ।

182. अंत में, एक छोटा सा विषय है जिसके बड़े पैमाने पर लाभकारी परिणाम हैं । वर्ष 2001 में ''टर्बो-प्रोप एयरक्राफ्ट को बेचे गए एविएशन टर्बाइन ईंधन'' को सीएसटी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत घोषित माल की सूची में शामिल किया गया था । 'टर्बो-प्रोप एयरक्राफ्ट का स्थान ऐसी नई गुणवत्ता के छोटे एयरक्राफ्ट ने ले लिया है, जिन्होंने बहुत ही छोटे विमान पत्तनों तथा देश के सुदूरवर्ती भागों में विमान सेवाएं देनी आरम्भ की हैं । अत: मैं ऐसे सभी छोटे विमानों को, जो अनुसूचित विमान सेवाओं द्वारा प्रचालित हैं और जिनकी अधिकतम 40,000 किलोग्राम से कम उड़ान भार क्षमता है, कवर करने के लिए प्रावधान को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं ।

183. कर सुधारों के साथ-साथ सरकार ने कर-प्रशासन पर अत्यधिक जोर दिया है । भारत में करों की वसूली की लागत विश्व के देशों में सबसे कम वालों में है । वर्ष 2007-08 के लिए अनेक प्रशासनिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । इनमें वार्षिक सूचना विवरणियों के कवरेज का विस्तार करना, और अधिक क्षेत्रों तक ''रिफन्ड बैंकर सिस्टम'' का विस्तार करना, अधिक बैंकों के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी माध्यम द्वारा भुगतान की सुविधा का विस्तार करना, कर निर्धारितियों की और श्रेणियों के लिए आय कर विवरणियों को इलैक्ट्रानिकी माध्यम से भरना अनिवार्य बनाना और नए कर दाताओं की बड़े पैमाने पर नई यूनिटों का सृजन करना शामिल है ।

184. प्रत्यक्ष करों पर मेरे कर प्रस्तावों से अनुमानत: 3,000 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होने की आशा है । अप्रत्यक्ष करों की दिशा में ये प्रस्ताव राजस्व तटस्थ हैं ।

XIV निष्कर्ष

185. अध्यक्ष महोदय, हमारे मानव और जेंडर विकास सूचकांक, उच्च वृद्धि के कारण कम नहीं हैं बल्कि वृद्धि पर्याप्त रूप से अधिक नहीं है । तीव्रतर आर्थिक वृद्धि ने हमें पुन: एक बार झंडा फहराने और हवा का रुख पहचान कर उसका फायदा उठाने का अवसर दिया है । आर्थिक वृद्धि के बिना मैं शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 1,00,000 छात्रवृत्तियों अथवा 1,00,000 रोजगारों की वचनबद्धता नहीं कर सकता था । ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए व्यापक भूमि जल पुनर्भरण कार्यक्रम या सामाजिक सुरक्षा का वचन नहीं दे सकता था ।

186. यूपीए सरकार ने बचतों और निवेश के वायदे पूरे किये हैं और अधिक बचतों को प्रोत्साहित करने तथा उन बचतों को और अधिक निवेशों में लगाने के अपने वायदे के प्रति वह वचनबद्ध है । इसने विकास के वायदे को पूरा किया और विकास को अत्यधिक व्यापक बनाने के अपने वायदे पर वचनबद्ध रहेगी । मेरा विश्वास है कि नीतियों के सही तालमेल से ही गरीब लोग उस विकास से लाभान्वित होंगे, जो बचतों और निवेश द्वारा संचालित होता है और यह इसकी संपूर्णता है । जैसा कि नोबल पुरस्कार विजेता डा. मुहम्मद युनुस, ने कहा है ''निर्धनता में तीव्रता से कमी लाने के लिए तीव्रतर विकास दर अनिवार्य है । इसके लिए अन्य कोई युक्ति नहीं है ।''

187. महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूं ।

एल. एम. वास, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Budget Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2007

No. F. 2(10) – B(D)/2007.—The following is published for general information :—

Budget 2007-2008

Speech of

P. CHIDAMBARAM

Minister of Finance

February 28, 2007

Mr. Speaker, Sir

It is my privilege to present the Budget for 2007-08.

I. A MID-TERM REPORT CARD ON THE ECONOMY

2. In November 2006, the UPA Government crossed the midpoint of its term of office. A midterm report card can now be presented. There are many pluses and a few minuses, and I shall deal with both candidly. The biggest plus is that

the growth rate of GDP has improved from 7.5 per cent in 2004-05 to 9 per cent (Quaick Estimate) in 2005-06 and, according to Advance Estimate, to 9.2 per cent in 2006-07. The average growth rate in the three years of the UPA Government is, therefore, 8.6 per cent. Thanks to this impressive performance, despite the poor start in 2002-03, the growth target set for the Tenth Plan of 8 per cent will be nearly achieved.

3. Manufacturing is the main driver of growth, and this augurs well for the future. In the three years of the UPA Government, the growth rate in manufacturing has accelerated from 8.7 per cent to 9.1 per cent and further to 11.3 per cent. The services sector continues to maintain impressive growth and has recorded, in the three years, a growth rate of 9.6 per cent, 9.8 per cent and 11.2 per cent respectively.

4. On the other hand, the agriculture sector has witnessed sharp ups and downs. Average growth during the Tenth Plan period is estimated at 2.3 per cent. Which is below the desired level of 4 per cent a year. About 115 million families are classified as farming families. Furthermore, a country with a large population has to be nearly self-sufficient in essential food items; otherwise supply constraints could upset macro economic stability and growth prospects. Hence, agriculture must top the agenda of the policy-makers and must hold the first charge on our resources. In a short while, I shall place before this House a number of proposals in this regard.

Income and Savings

5. To continue with the report card, per capita income in 2005-06, in real terms, increased by 7.4 per cent, and the savings rate has been estimated at 32.4 per cent and the investment rate at 33.8 per cent. Intuitively, I belive that these high raes have continued in the current year too.

6. The UPA Government has remained committed to economic reforms, fiscal prudence and monetary stability.

7. Revenues are buoyant for the third year in succession. We have garnered additional revenues and, as Honourable Members will notice presently, I have put these revenues to good use to promote inclusive growth, equity and social justice-goals that are at the core of the National Common Minimum Programme (NCMP) and close to the hearts of the UPA, its Chairperson and the Prime Minister.

Outlook on Inflation

8. Until February 2, 2007, bank credit, year on year, had grown by 29.6 per cent. Money supply (M3) had expanded by 21.3 per cent. Foreign exchange reserves stood at US$ 180 billion. While these are concomitant features of high growth, it cannot be denied that these monetary trends have put pressure on prices. Golbal commodity prices have also exerted pressure on domestic prices. At the same time, supply constraints have emerged in some essential commodities such as wheat, pulses and edible oils. Consequently, average inflation in 2006-07 is estimated at between 5.2 and 5.4 per cent, which is higher than 4.4 per cent last year. I wish to reiterate Government's concern over inflation. Government has already taken a number of measures on the fiscal, monetary and supply sides to maintain price stability and, if required, will not hesitate to take more measures. When the UPA Government assumed office in 2004, the inflation graph was on the rise; but we succeeded in moderating inflation and we are confident that we can moderate the present inflationary trend too.

II. BHARAT NIRMAN AND THE FLAGSHIP PROGRAMMES

9. Bharat Nirman remains the cornerstone of the Government's policy. I am glad to report that in the current financial year:

- Additional irrigation potential of 2,400,000 hectares, including 900,000 hectares under AIBP, will be created;
- Drinking water has been provided to 55,512 habitations until December 2006 against a target of 73,120 habitations;
- Until December 2006, 12,198 kilometres of rural roads have been completed. The separate window under RIDF will augment funds for the programme by Rs. 4,000 crore a year;
- 783,000 rural houses have been constructed up to December 2006 and 914,000 houses are under construction, and the annual target of 1,500,000 houses is likely to be exceeded;
- 19,758 villages have been covered so far under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana;
- 15,054 villages have been provided with a telephone against the target of 20,000 villages, and the balance will be covered by the end of the year.

Honourable Members will note that Bharat Nirman continues to make impressive progress.

10. The eight flagship programmes of the UPA Government will continue to receive high priority. Presently, I shall refer to these programmes in some detail.

III. HERALDING THE ELEVENTH FIVE YEAR PLAN

11. The year 2007-08 will mark the beginning of the Eleventh Plan. The declared objective is "Faster and More Inclusive Growth". I can state with confidence that, on the eve of the Plan, the eocnomy is in a stronger position than ever before. It therefore behoves us to set higher goals. The Approach Paper to the Eleventh Plan states that the Plan "will aim at putting the economy on a sustainable growth trajectory with a growth rate of approximately 10 per cent by the end of its period." Among the other objectives of the Plan are growth of 4 per cent in the agriculture sector, faster employment creation, reducing disparities across regions and ensuring access to basic physical infrastructure as well as health and education services to all. I have kept these objectives in mind while allocating resources to various sectors.

Gross Budgetary Support

12. Notwithstanding some constraints, I propose to increase substantially the Gross Budgetary Support (GBS) for the Plan. In 2006-07, the GBS was fixed at Rs. 172,728 crore and, of this, support to the Central Plan was Rs. 131,284 crore. GBS for 2007-08 will be increased to Rs. 205,100 crore. Out of this, the Central Plan will receive Rs. 154,939 crore.

Allocations for Major Sectors

13. For Bharat Nirman, as against Rs. 18,696 crore (including the NER component) in 2006-07, I propose to provide Rs. 24,603 crore in 2007-08, which marks an increase of 31.6 per cent.

14. The education and health sectors will also receive substantial funds. In 2007-08, I propose to enhance the allocation for education by 34.2 per cent to Rs. 32,352 crore and for health and family welfare by 21.9 per cent to Rs. 15,291 crore.

Sarva Shiksha Abhiyan and Mid-day Meal Scheme

15. In allocating resources, school education must have primacy. Hence, I propose to increase the allocation for school education by about 35 per cent from Rs. 17,133 crore in 2006-07 to Rs. 23,142 crore in 2007-08.

16. Out of this amount, Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) will be provided Rs. 10,671 crore. Further, I propose to increase the provision for strengthening teachers training institutions from Rs. 162 crore to Rs. 450 crore. Next year, we will appoint 200,000 more teachers and construct 500,000 more class-rooms.

17. The Mid-day Meal Scheme will be provided Rs. 7,324 crore next year. In addition to covering children in primary classes, beginning 2007-08, we propose to cover children in upper primary classes in 3,427 educationally backward blocks.

18. The transfer to Parambhik Shiksha Kosh will increase from Rs. 8,746 crore to Rs. 10,393 crore.

19. As more students complete upper primary classes, it is necessary to increase access to secondary education. Schemes for this purpose are under formulation, and I propose to double the provision for secondary education from Rs. 1,837 crore in 2006-07 to Rs. 3,794 crore in 2007-08.

Means-cum-Merit Scholarships

20. While the SSA has improved the enrolment ratio in schools to 96 per cent, the drop out ratio continues to be high. The critical year appears to be transition from class VIII to class IX. In order to arrest the drop out ratio and encourage students to continue their education beyond class VIII, I propose to introduce a National Means-cum-Merit Scholarship Scheme. Selection will be made through a national test from among students who have passed class VIII. Each student will be given Rs. 6,000 per year for study in classes IX, X, XI and XII. I propose that 100,000 scholarships may be awarded every year. In order to fund this programme, I intend to create a corpus fund of Rs. 750 crore this year, and add a like amount to the fund every year over the next three years. Accordingly, a sum of Rs. 750 crore will be placed with the State Bank of India, and the yield from the fund will be used for awarding the scholarships.

Drinking Water and Sanitation

21. 55,512 habitations and 34,000 schools have been provided drinking water supply till December, 2006 under the Rajiv Gandhi Drinking Water Mission. More ambitious targets have been set for 2007-08 to deal with both non-coverage and slippage. I propose to enhance the allocation for the Mission from Rs. 4,680 crore in 2006-07 to Rs. 5,850 crore in 2007-08.

22. As regards the Total Sanitation Campaign, I propose to increase the provision from Rs. 720 crore this year to Rs. 954 crore next year.

Health Sector : National Rural Health Mission

23. In the second year of its implementation, the National Rural Health Mission (NRHM) is on schedule to meet its timelines. The institutional integration of all the health schemes at the district and lower levels has been achieved. All

districts in the country will complete preparation of District Health Action Plans by March 2007. The major emphasis will be on mother and child care and on the prevention and treatment of communicable diseases such as tuberculosis and malaria. Through Monthly Health Days (MHD) organised at Anganwadi centres, convergence is sought to be achieved among various programmes such as immunization, ante natal care as well as nutrition and sanitation.

24. I am happy to report that 320,000 Associated Social Health Activists (ASHAs) have been recruited and over 200,000 have received orientation training. Besides, 90,000 link workers have been selected by the States. With trained ASHAs in place, I am confident there will be significant improvement in health care in rural areas. The Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Sidha and Homeopathy (AYUSH) systems are also being mainstreamed into the health delivery system at all levels. I propose to increase the allocation for NRHM from Rs. 8,207 crore in 2006-07 to Rs. 9,947 crore in 2007-08.

HIV/AIDS

25. Government has brought HIV/AIDS out of the closet and promised bold and determined efforts to achieve zero-level growth of the disease. The epidemic will be deemed 'stabilised' if the prevalence rate is less than one per cent of the population. National Aids Control Programme (NACP)-III, starting in 2007-08 and building on NACP-I and NACP-II, will target the high risk groups in all the States. We will expand access to condoms and ensure universal access to blood screening and safe blood. More hospitals will provide treatment to prevent transmission of HIV/AIDS from mother to child. Support will be given to the protocol on paediatric dosage developed by Indian doctors and launched in November 2006. For the year 2007-08, I propose to step up the provision for the AIDS control programme to Rs. 969 crore.

Polio

26. Last year, I had expressed the hope that polio will be eliminated from the country by December 2007. However, there was an outbreak in Western Uttar Pradesh in early 2006. The strategy for polio eradication has been revised. The number of polio rounds will be increased, monovalent vaccine will be introduced, and there will be intensive coverage in the 20 high risk districts of Uttar Pradesh and 10 districts of Bihar. The programme has been integrated into the NRHM. The ASHAs and the Anganwadi workers will visit every household and track every child for the immunization programme. To achieve the goal of eliminating polio, I propose to provide Rs. 1,290 crore in 2007-08.

Integrated Child Development Services

27. In the second phase of expansion of the Integrated Child Development Services (ICDS), Government has sanctioned 173 ICDS projects, 107,274 Anganwadi centres and 25,961 mini-Anganwadi centres. Government is committed to expand the scheme in order to cover all habitations and settlements during the eleventh Plan and to reach out to pregnant women, lactating mothers and all children below the age of six. I propose to increase the allocation for ICDS from Rs. 4,087 crore in 2006-07 to Rs. 4,761 crore in 2007-08.

National Rural Employment Guarantee Scheme

28. The National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) was lanunched on February 2, 2006. The pace of implementation varies from State to State. Since NREGS is a demand-driven scheme carrying a legal guarantee of employment, the budget allocation would have to be supplemented according to need. I therefore propose to make an initial allocation of Rs. 12,000 crore (including NER component) for NREGS, I am also happy to announce that NREGS will be expanded from the current level of 200 districts to 330 districts. In addition, I have provided Rs. 2,800 crore for Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY) for rural employment in the districts not covered by NREGS.

29. Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) is intended to promote self-employment among the rural poor through Self Help Groups (SHG). I propose to strengthen this programme by increasing the allocation from Rs. 1,200 crore in the current year to Rs. 1,800 crore (including NER component) next year.

Urban Unemployment

30. The issue of urban unemployment and poverty alleviation is equally critical. Hence, I propose to increase the allocation for Swarna Jayanti Shahari Rojgar Yojana from Rs. 250 crore in 2006-07 to Rs. 344 crore next year.

Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission

31. The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) has evoked a positive response from State Governments. As on date, 538 projects with a total cost of Rs. 23,950 crore have been sanctioned in sectors such as water supply, sanitation, transport, road and housing in many cities spread over several States. I propose to enhance the allocation from Rs. 4,595 crore in 2006-07 to Rs. 4,987 crore 2007-08.

Targeted Public Distribution System and Antyodaya Anna Yojana

32. The issue prices of foodgrains under the Public Distribution System (PDS) and for the beneficiaries of the Antyodaya Anna Yojana have been retained. A Plan scheme for evaluation, monitoring, management and strengthening of the targeted PDS will be implemented in 2007-08, and this will include computerisation of the PDS and an integrated information system in the Food Corporation of India.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes

33. Continuing the practice that was started in 2005-06, a separate statement on the schemes for the welfare of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) is placed in the Budget documents. The allocation in 2007-08 for SCs and STs has been substantially enhanced. In respect of schemes benefiting only SCs and STs, I have increased the allocation to Rs. 3,271 crore. In respect of schemes with at least 20 per cent of the benefits earmarked for SCs and STs, I have increased the allocation to Rs. 17,691 crore.

34. SC and ST students stydying in M. Phil and Ph.D courses are supported by the Rajiv Gandhi National Fellowship Programme. I propose to enhance the allocation from Rs. 35 crore in 2006-07 to Rs. 88 crore in 2007-08.

Post-Matric Scholarships

35. There is a post-matric scholarship programme for SC and ST students. I propose to increase the provision for these scholarships from Rs. 440 crore in 2006-07 to Rs. 611 crore in 2007-08. I also propose to make a separate provision of Rs. 91 crore for similar scholarships to be awarded to students belonging to socially and educationally backward classes.

Minorities

36. Last year, I made a modest contribution of Rs. 16.47 crore to the equity of the National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC). Following the Sachar Committee report, NMDFC would be required to expand its reach and intensify its efforts. Hence, I propose to provide a further sum of Rs. 63 crore to the share capital of NMDFC.

37. There are a number of districts with a concentration of minorities. I propose to make a provision of Rs. 108 crore for a multi-sector development programme in these districts.

38. Three scholarship programmes are being implemented for students belonging to minority communities. I propose to make the following allocations :

Pre-matric scholarships	Rs. 72 crore
Post-Matric scholarships	Rs. 90 crore
Merit-cum-Means Scholarships at graduate and post-graduate levels	Rs. 48.60 crore

Women

39. There is growing awareness of gender sensitivities of budgetary allocations. 50 ministries/departments have set up gender budgeting cells. For 2007-08, 27 ministries/departments and 5 Union Territories covering 33 demands for grants have contributed to a statement placed in the budget papers. The outlay for 100 per cent women specific programmes is Rs. 8,795 crore and for schemes where at least 30 per cent is for women specific programmes is Rs. 22,382 crore. We have made a sincere effort to remove the errors that were pointed out in last year's statement.

North Eastern Region (NER)

40. The total budget allocation in 2007-08 for the North Eastern Region, culled out from allocations under different ministries/departments, has increased from Rs. 12,041 crore in 2006-07 to Rs. 14,365 crore in 2007-08. This includes Rs. 1,380 crore provided to the Ministry of Development of North Eastern Region (DONER). The new industrial policy for NER, with suitable fiscal incentives, will be in place before March 31, 2007.

Supplement to the GBS

41. I have, so far, outlined the allocations under what may be called Plan 'A' which has a resource basket of Rs. 205,100 crore. In consultation with the Planning Commission, I have also drawn up Plan 'B'. Since the Eleventh Plan will begin on April 1, 2007, we recognize that there will be a need to take new initiatives in critical areas. Additional resources will be needed once the proposals are finalised and the pace of expenditure builds up. Therefore, I shall endeavour to find additional resources through better tax administration to the extent to Rs. 7,000 crore during the course of the year. I have been advised by the Planning Commission that these additional funds, once voted by this House, will be allocated among sectors such as agriculture, rural development, health, women and child development, urban infrastructure, water resources, etc.

42. I also Plan 'C'. Under Plan 'C', I propose to tap into resources available outside the Budget and leverage them for the purpose of investment, especially in the infrastructure sector. I shall deal with this subject a little later.

IV. Agriculture

43. I shall now take up our main challenge: agriculture. I may recall the words of Jawaharlal Nehru, who said "Everything else can wait, but no agriculture".

44. The draft National Policy for Farmers submitted by the National Commission on Farmers is under consideration. Meanwhile, I have number of proposals to improve the economic viability of farming and ensure that farmers earn a minimum net income.

Farm Credit

45. Farm credit continues to grow at a satisfactory pace. The goal of doubling farm credit in three years was achieved in two years. The target of Rs. 175,000 crore set for 2006-07 will be exceeded comfortably and is likely to reach Rs. 190,000 crore. This year, until December 2006, 53.37 lakh new farmers were brought into the institutional credit system. For 2007-08, I propose to fix a target of Rs. 225,000 crore as farm credit and an addition of 50 lakh new farmers to the banking system.

46. The two per cent interest subvention scheme for short-term crop loans will continue in 2007-08, and I am making a provision of Rs. 1,677 crore for that purpose.

47. A special plan is being implemented over a period of three years in 31 especially distressed districts in four States of the country involving a total amount of Rs. 16,979 crore. Of this, about Rs. 12,400 crore will be on water related schemes. In order to provide subsidiary income to the farmer, the special plan includes a scheme for induction of high yielding milch animals and related activities. I propose to provide Rs. 153 crore for this scheme.

Agricultural Indebtedness

48. Government had appointed a Committee under Dr. R. Radhakrishna to examine all aspects of agricultural indebtedness. The Committee has held wide ranging consultations across the country and is in the process of finalising its recommendations. Government will act on the report as soon as it is received.

A Mission for Pulses

49. Government is concerned about the stagnation in the production and productivity of pulses. Critical deficiency is the availability and quality of certified seeds. I therefore propose to expand the Integrated Oilseeds, Oil palm, Pulses and Maize Development programme. There will be a sharper focus on scaling up the production of breeder, foundation and certified seeds. The Indian Institute of Pulses Research (IIPR), Kanpur, the National and State level seeds corporations, agricultural universities, ICAR centres, KRIBHCO, IFFCO and NAFED as well as large private sector companies will be invited to submit plans to scale up the production of seeds. Government will fund the expansion of IIPR, Kanpur, and offer the other producers a capital grant or concessional financing in order to double the production of certified seeds within a period of three years.

Plantation Sector

50. A Special Purpose Tea Fund has been launched for re-plantation and rejuvenation of tea. Government will soon put in place similar financial mechanisms for coffee, rubber, spices, cashew and coconut.

Accelerated Irrigation Benefit Programme

51. The Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) has been revamped in order to complete more irrigation projects in the quickest possible time. 35 projects are likely to be completed in 2006-07 and additional irrigation potential of 900,000 hectares will be created. As against an outlay of Rs. 7,121 crore in 2006-07, the outlay for 2007-08 will be increased to Rs. 11,000 crore. Of this, the grant component to State Governments will be Rs. 3,580 crore, an increase from Rs. 2,350 crore.

Rainfed Area Development Programme

52. The National Rainfed Area Authority was established a few months ago to coordinate all schemes relating to watershed development and other aspects of land use. I propose to allocate Rs. 100 crore for the new Rainfed Area Development Programme.

Water Resources Management: Restoring Water Bodies

53. Honourable Members will recall that, in March 2005, a pilot project to repair, renovate and restore water bodies was launched in 13 States. I am happy to inform the House that the World Bank has signed a loan agreement with Tamil

Nadu for Rs. 2,182 crore to restore 5,763 water bodies having a command area of 400,000 hectares. An agreement for Andhra Pradesh is expected to be concluded in March 2007 and will cover 3,000 water bodies with a command area of 250,000 hectares. Preparation of similar projects for Karnataka, Orissa and West Bengal are at different stages and at least two more agreements are likely to be concluded before June 2007. I would urge other State Governments to come forward with proposals so that the whole country can be covered within the next two years.

Ground Water Recharge

54. Depletion of ground water has assumed grave proportions. The Central Ground Water Board has identified 1,065 assessment blocks in the country as 'over-exploited' or 'critical'. Over 80 per cent of these blocks are in 100 districts in seven States. The strategy for ground water recharge is to divert rain water into 'dug wells'. Each structure will cost about Rs. 4,000. The requirement is seven million structures, including about two million structures on land belonging to small and marginal farmers. I propose to provide 100 per cent subsidy to small and marginal farmers and 50 per cent subsidy to other farmers. Ministry of Water Resources will finalise the scheme shortly. In anticipation, I intend to transfer a sum of Rs. 1,800 crore to NABARD. The amount will be held in escrow and will be disbursed through the lead bank of the District concerned to the beneficiaries.

Training of Farmers

55. With minimum instruction and training, our farmers will easily absorb good water management practices. I therefore propose that the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) may set up one teaching-cum-demonstration model of water harvesting in each of 32 selected State Agricultural Universities and ICAR institutes. Each institution will train 100 trainers and 1,000 farmers every year in two-week and one-week programmes respectively. Based on estimates of recurring costs, I intend to provide an interest free loan of Rs. 3 crore to each institution to create a corpus fund. The yield from the fund will be used for implementing the training programme. The total cost is estimated at Rs. 100 crore.

Extenstion System

56. The green revolution of the 1960s was brought about by thousands of agricultural extension workers who worked side by side with our farmers under a programme called Training and Visit (T&V). Sadly, the extension system seems to have collapsed. In order to revive extension work, the Ministry of Agriculture will, in consultation will State Governments, draw up a new programme that will replicate T&V with suitable changes.

57. The Agriculture Technology Management Agency (ATMA) that is now in place in 262 Districts will be extended to another 300 Districts in 2007-08. I propose to enhance the provision for ATMA from Rs. 50 crore to Rs. 230 crore next year.

Fertiliser Subsidies

58. I had budgeted Rs. 17,253 crore for fertiliser subsidies in 2006-07. According to Revised Estimates, this will rise to Rs. 22,452 crore, and there is a demand for more money. While fertilisers should indeed be subsidised, we must find an alternative method of delivering the subsidy directly to the farmer. The fertiliser industry has agreed to work with the Department of Fertilisers to conduct a study and find a solution. Based on the report, Government intends to implement a pilot programme in at least one district in each State in 2007-08.

Agricultural Insurance

59. The National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) will be continued in its present form for Kharif and Rabi 2007-08. I propose to make a provision of Rs. 500 crore for the scheme.

60. Agricultural Insurance Corporation (AIC) has been running a pilot weather insurance scheme since Kharif 2004 and it appears to be a more promising risk mitigation scheme. Hence, Government will ask AIC to start a weather based crop insurance scheme on a pilot a basis in two or three States, in consultation with the State Governments concerned, as an alternative to the NAIS. The scheme will be operated on an acturial basis with an element of subsidy. I intend to allocate Rs. 100 crore for this purpose in 2007-08.

National Bank for agriculture and Rural Development (NABARD)

61. NABARD provides refinance to cooperative institutions. As the volume of farm credit increases and the Viaidyanathan Committee recommendations for reform of rural credit cooperatives are implemented, the demand for refinance will increase. In order to augment its resources, I propose to allow NABARD to issue rural bonds to the extent of Rs. 5,000 crore. These bonds will be guaranteed by the Government and will be eligible for suitable tax exemption.

Rural Infrastructure Development Fund

62. The Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) continues to sanction and disburse funds to State Governments. In 2006-07, out of a corpus of Rs. 10,000 crore, NABARD has so far issued sanctions for Rs. 8,440 crore and will achieve its target. Keeping in view the growing demand for these funds, I propose to raise the corpus of RIDF-XIII in 2007-08 to Rs. 12,000 crore. I would urge State Governments to use these funds primarily in the distressed districts of the State.

63. A separate window for rural roads under RIDF was opened with Rs. 4,000 crore. Against this, projects for Rs. 2,311 crore have been sanctioned in 2006-07. I propose to continue the separate window under RIDF-XIII in 2007-08 with a corpus of Rs. 4,000 crore.

Social Security

64. One of the commitments made in the NCMP is that Government will introduce a social security scheme for unorganised workers. A committee chaired by Dr. Arjun Sengupta has given its report which is under consideration. Pending a decision, in order to signal the UPA Government's concern for the welfare of unorganised workers, I propose to make a beginning. I propose to extend death and disability insurance cover through Life Insurance Corporation of India (LIC), to rural Landless households under a new scheme called 'Aam Admi Bima Yojana' (AABY). According to NSS Report No. 491, the estimate of such households is about 1.5 crore. By end March 2007, 70 lakh households will be covered through existing schemes of the LIC with the support of some State Governments and the social security fund with the LIC. Under AABY. I propose to cover the rural landless households which enjoy no cover at all today, and the number may be actually more than what is indicated in the NSS report. The head of the family or one earning member in the family will be insured. The Central Government will bear 50 per cent of the premium of Rs. 200 per year per person and I would urge the State Governments to come forward to bear the other 50 per cent on behalf of the beneficiaries. Taking into account the annual cost to the Central Government, I intend to place a sum of Rs. 1,000 crore in a fund that will be maintained by LIC. I propose to finalise the scheme in consultation with State Governments and begin to implement it in 2007-08.

65. Mr. Speaker, Sri, I have devoted the last 15 minutes or so to agriculture. There is no dearth of schemes; there is no dearth of funds. What needs to be done is to deliver the intended outcomes. Saint Tiruvalluvar watches over us and warns:—

"Uzhvinar Kai Madangin Illai Vizhaivathoom Vittame Enbarkum Nilai"

[If ploughmen keep their hands folded

Even sages claiming renunciation cannot find salvation]

V. Investment

66. All indicators point to an accelerating rate of investment in the economy. For example, gross domestic capital formation (GDCF) in 2005-06 grew by 23.7 per cent over the previous year to Rs. 11,47,254 crore. I believe that this trend continues in 2006-07. In April-January, 2006-07, foreign direct investment amounted of US$ 12.5 billion and outpaced portfolio investment which was RS$ 6.8 billion.

67. Central Pubic Section Enterprises (CPSEs) will, through internal and extra budgetary resources, invest Rs. 165,053 crore in 2007-08. Government will provide equity support of Rs. 16,361 crore and loans of Rs. 2,970 crore to CPSEs.

68. Further, in the current year, we have restructured eight CPSEs with a cash infusion of Rs. 1,590 crore and non-cash sacrifices of Rs. 1,612 crore.

VI. Infrastructure

Power

69. Electricity generation has recorded a growth rate of 7.5 per cent in April-December this year. However, as we complete the Tenth Plan, we would have added only 23,163 MW of additional capacity in the five year period including 16,339 MW added in the three years begining 2004-05. Hence, it is imperative that we take new initiatives.

70. The Ministry of Power has awarded two Ultra Mega Power Projects (UMPP) in Sasan and Mundra. Seven more UMPPs are under process and we are confident that at least two more will be awarded by July 2007. Other initiatives taken by the Ministry of Power include facilitating setting up of merchant power plants by private developers and private participation in transmission projects.

71. Besides, the Accelerated Power Development and Reforms Project (APDRP) has reduced significantly Aggregate Technical and Commercial (ATC) losses in 213 towns. APDRP is being restructured to cover all District headquarters

and towns with a population of more than 50,000. I propose to increase the budgetary support for APDRP from Rs. 650 crore in 2006-07 to Rs. 800 crore next year.

Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana

72. Having regard to the pace of implementation under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana and the annual target. I propose to increase the allocation from Rs. 3000 crore in 2006-07 to Rs. 3,983 crore in 2007-08.

Coal

73. Following the announcement last year, 26 coal blocks with reserves of 8,581 million tonnes and four lignite blocks with reserves of 755 million tonnes have been allotted, up to December 2006, to Government companies and approved end users. The definition of specified end use will be enlarged to include underground coal gasification and coal liquefaction.

National Highways

74. Work on the golden quadrilateral is nearly complete and there is considerable progress in the North-South, East-West corridor project which is expected to be completed by 2009. NHDP-III, NHDP-V and NHDP-VI are in advanced stages of planning or implementation. So far, National Highways Authority of India (NHAI) has given Rs. 2,072 crore as viability gap funding but has also received Rs. 1,900 crore as negative grant. The private sector investment leveraged under NHDP is Rs. 25,366 crore. Under the programme for the North Eastern Region (SARDP-NE), 450 kilometres have been awarded in 2006-07 and the balance will be awarded in 2007-08. I propose to increase the provision for the National Highway Development Programme (NHDP) from Rs. 9,945 crore in 2006-07 to Rs. 10,667 crore next year.

75. The road-cum-rail bridge at Munger, Bihar, over the Ganga, has been taken up as a national project. Likewise, the road-cum-rail bridge at Bogibeel, Assam, over the Brahmaputra, will be taken up as a national project.

Public Private Partnership and Viability Gap Funding

76. The Public Private Partnership (PPP) model has enabled greater private sector participation in the creation and maintenance of infrastructure. So far, under the viability gap funding scheme, 37 proposals have been received of which 21 proposals have been granted 'in-principle' approval with a total project cost of Rs. 9,842 crore and an estimated viability gap funding of Rs. 2,521 crore. The pace is slow, and there is a need to adopt a more aggressive approach for preparing a shelf of bankable projects that can be offered for competitive bidding. Apart from the steps already taken for capacity building and engaging consultants, I intend to set up a revolving fund with a corpus of Rs. 100 crore to quicken project preparation. The fund will contribute up to 75 per cent of the preparatory expenditure in the form of interest free loan that will be eventually recovered from the successful bidder. Guidelines for operating the fund will be announced in due course.

VII. INDUSTRY

Petroleum and Natural Gas

77. Energy security is high on the Government's agenda. In the six rounds of New Exploration Licensing Policy (NELP) so far, 162 production sharing contracts have been awarded. Indian and foreign companies have already made an investment of Rs. 97,000 crore in exploration. Similarly, after three rounds of bidding, 23 coal bed methane blocks have been awarded for exploration.

Textiles

78. A rejuvenated textile industry is geared to meet the global challenge. 26 parks have been approved so far out of 30 sanctioned under the Scheme for Integrated Textiles Parks (SITP). I propose to increase the provision for these parks from Rs. 189 crore in 2006-07 to Rs. 425 crore in 2007-08.

79. I am also glad to announce that the Technology Upgradation Fund (TUF) scheme will be continued during the Eleventh Plan. Against a provision of Rs. 535 crore in 2006-07, I propose to provide Rs. 911 crore in 2007-08. As before, handlooms will be covered under the TUF scheme.

Handlooms

80. A cluster approach for the development of the handloom sector was introduced in 2005-06 and 120 clusters have been selected. 273 new yarn depots have been opened in the current year and the Handloom mark was launched. Government proposes to take up an additional 100—150 clusters in 2007-08. The 12 schemes that are now implemented will be grouped into five schemes in the Eleventh Plan period. The health insurance scheme has so far covered 300,000 weavers

and will be extended to more weavers. The scheme will also be enlarged to include ancillary workers. I propose to enhance the allocation for the sector from Rs. 241 crore in 2006-07 to Rs. 321 crore next year.

Small and Medium Enterprises

81. Following the credit policy for small and medium enterprises (SME) announced in August 2005, outstanding credit to the SME sector increased from Rs. 135,200 crore at end December 2005 to Rs. 173,460 crore at end December 2006. While encouraging banks to lend more to the SME sector, I propose to ask banks to have regard to the credit rating acquired by an SME while fixing the interest rate.

Coir Industry

82. Coir is an eco-friendly fibre. The coir industry provides employment to a large number as well as earns valuable foreign exchange. I am happy to announce a scheme for the modernisation and technology upgradation of the coir industry with special emphasis to major coir producing States such as Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Orissa. I propose to make a provision of Rs. 22.50 crore.

VIII. SERVICES SECTOR

Foreign Trade

83. Our merchandise exports crossed the milestone of US $ 100 billion in 2005-06 and are expected to cross another milestone of US $ 125 billion by the end of the current fiscal. Foreign trade is growing at a rate more than twice the growth rate of GDP. Government will continue to follow export friendly policies.

Tourism

84. I propose to increase the provision for building tourist infrastructure from Rs. 423 crore in 2006-07 to Rs. 520 crore in 2007-08.

IX. FINANCIAL SECTOR

Banking

85. In addition to the important legislative measures now before Parliament, Government proposes to take a number of initiatives in banking and insurance.

86. Government proposes to acquire RBI's equity holding in State Bank of India I have provided a sum of Rs. 40,000 crore for this purpose, but the transaction will be deficit neutral to the Government.

87. The Differential Rate of Interest (DRI) scheme provides finance at a rate of 4 per cent to the weaker sections of the community engaged in gainful occupations. I propose to rise the limit of the loan from Rs. 6,500 to Rs. 15,000 and the limit of the housing loan from Rs. 5,000 to Rs. 20,000 per beneficiary.

Regional Rural Banks

88. Regional Rural Banks (RRBs) have emerged as the third arm for delivering rural credit, and the sponsor banks have assured me that RRBs are willing to take on greater responsibilities. The Committee on Financial Inclusion, chaired by Dr. C. Rangarajan, has also made certain recommendations concerning RRBs. I, therefore, propose to :

- ask RRBs to undertake an aggressive branch expansion programme and, in 2007-08, open at least one branch in the 80 uncovered districts of the country;
- extend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securitisation of Interest (SARFAESI) Act to loans advanced by RRBs;
- permit RRBs to accept NRE/FCNR deposits ; and
- recapitalize, in a phased programme, the RRBs which have a negative net worth.

Housing Loans

89. The National Housing Bank (NHB) will shortly introduce a novel product for senior citizens : a 'reverse mortgage' under which a senior citizen who is the owner of a house can avail of a monthly stream of income against the mortgage of his/her house, while remaining the owner and occupying the house throughout his/her lifetime, without repayment or servicing of the loan.

90. Our people want housing loans. Banks and housing finance companies that lend against mortgages would have greater comfort if the mortgage can be guaranteed through a three way contract among borrower, lender and guarantor. Regulations will be put in place to allow the creation of mortgage guarantee companies.

Insurance

91. On December 6, 2006, Rashtrapatiji launched an exclusive health insurance scheme for senior citizens offered by National Insurance Company. I have asked the other three public sector insurance companies to offer a similar product to senior citizens, and they have agree to do so in 2007-08.

92. The Micro Financial Sector (Development and Regulation) Bill as well as a comprehensive Bill to amend the insurance laws will be introduced in the Budget Session.

Financial Inclusion

93. Financial inclusion is the process of ensuring access to timely and adequate credit and financial services by vulnerable groups at an affordable cost. The Committee on Financial Inclusion has given an interim report. While we await the final report, Government has decided to implement, immediately, two recommendations. The first is to establish a Financial Inclusion Fund with NABARD for meeting the cost of developmental and promotional interventions. The second is to establish a Financial Inclusion Technology Fund to meet the costs of technology adoption. Each fund will have an overall corpus of Rs. 500 crore, with initial funding to be contributed by the Central Government, RBI and NABARD.

Capital Markets

94. The capital market is an important instrument for intermediating financial resources. Recognising the strength of the Indian capital market, the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) has decided to hold its annual conference in Mumbai in April 2007. In line with measures announced every year to strengthen the market, I propose to :

- make PAN the sole identification number for all participants in the securities market with an alpha-numeric prefix or suffix to distinguish a particular kind of account;
- take forward the idea of Self Regulating Organisations (SRO) for different market participants under regulations that will be made by SEBI and, if necessary, supported by an enabling law;
- promote the flow of investment to the infrastructure sector by permitting mutual funds to launch and operate dedicated infrastructure funds;
- converge the different regulations that allow individuals and Indian Mutual Funds to invest in overseas securities by permitting individuals to invest through Indian Mutual Funds;
- allow short selling settled by delivery, and securities lending and borrowing to facilitate delivery, by institutions;
- put in place an enabling mechanism to permit Indian companies to unclok a part of ther holdings in group companies for meeting their financing requirements by issue of Exchangeable Bonds.

Innovative Financing for Infrastructure

95. The minimum obligation of States to borrow from the National Small Savings Fund (NSSF) has been brought down to 80 per cent of net collections. Repayments of past NSSF loans by the Central and State Governments have also commenced from 2005-06, making available resources for long term lending. I therefore propose that these funds may also be borrowed from NSSF by India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL).

96. An initiative that has borne fruit is the launch of the US $5 billion infrastructure financing initiative by Citigroup, Blackstone, IDFC and IIFCL.

97. A committee chaired by Shri Deepak Parekh has made a number of recommendations for financing infrastructure. One of the recommendations is to use a small part of the foreign exchange reserves without the risk of monetary expansion.

The Committee has suggested the establishment of two wholly-owned overaseas subsidiaries of IIFCL with the following objectives :

(i) to borrow funds from the RBI and lend to Indian companies implenting infrastructure projects in India, or to co-finance their ECBs for such projects, solely for cpaital expenditure outside India; and

(ii) to borrow funds from the RBI, invest such funds in highly rated collateral securities, and provide 'credit wrap' insurance to infrastructure projects in India for raising resources in international markets.

The loans by RBI to these two subsidiary companies will be guaranteed by the Government of India and the RBI will be assured of a return higher than the average rate of return on its incremental investment. Government proposes to examine the legal and regulatory aspects of the recommendation, in consultation with RBI, in order to find an innovative method of enhancing the financial resources for infrastructure.

X. OTHER PROPOSALS

Defence Expenditure

98. I propose to increase the allocation for Defence to Rs. 96,000 crore. This will include Rs. 41,922 crore for capital expenditure. Needless to say, any additional requirement for the security of the nation will be provided.

Information Technology

99. Government has launched an ambitious programme for e-governance. The goal is to improve efficiency, convenience, assessibility and transparency in Government functions and take Government services to the common citizen. I propose to increase the allocation for e-governance from Rs. 395 crore in 2006-07 to Rs. 719 crore in 2007-08. The Central Government supports e-governance action plans at State levels, and I propose to increase the allocation for such support from Rs. 300 crore in 2006-07 to Rs. 500 crore in 2007-08. I also propose to provide Rs. 33 crore for a new scheme of manpower development for the software export industry.

Backward Regions Grant Fund

100. The Backward Regions Grant Fund received Rs. 5,000 crore in 2006-07. I propose to increase the allocation to Rs. 5,800 crore in 2007-08. This will finance two components, one pertaining to 250 districts and the other pertaining to the special plan for Bihar. KBK districts, of Orissa, which are included in the 250 districts, will continue to receive the same quantum of assistance as they have been receiving in the past.

Mumbai as a Financial Centre

101. The High Powered Expert Committee to make Mumbai a regional financial centre has submitted its report recently. I intend to place the report in the public domain and obtain feedback. It is my hope that we would be able to build a consensus on the key recommendations of the Committee, promote a world class financial centre in Mumbai, and realise the objective of making 'financial services' the next growth engine for India.

Vocational Education Mission

102. To sustain a high level of economic growth, it is essential to have a reservior of skilled and trained manpower. Shortages have already emerged in a number of sectors. Moreover, we can take advantage of the demographic dividend thrown up by an increase in the working age population only if our young men and women have the required skills. The Prime Minister spoke of a Vocational Education Mission in his Independence Day Address in 2006. A task force in the Planning Commission is chalking out strategies for vocational education programmes. Alternate models may be adopted, but the approach will be based on public-private partnership. I propose to make an initial provision of Rs. 50 crore for beginning work on this mission.

Upgradation of ITIs

103. Honourable members will recall that Government had taken up a programme for upgradation of 500 ITIs over five years beginning 2005. Revised courses in the first lot of 100 upgraded ITIs were started in August 2005 and in the second lot of 100 upgraded ITIs in August 2006. I except that another 300 ITIs will be covered by August 2009. That would still leave 1,396 Government ITIs.

104. I propose that the 1,396 ITIs be upgraded into centres of excellence in specific trades and skills under public-private partnership. Under the proposed scheme, the State Government, as the owner of the ITI, will continue to regulate admissions and fees; the new management will be given academic and financial

autonomy; and the Central Government will provide financial assistance by way of seed money. ITIs will be encouraged to start a second shift. Once a tripartite MoU is signed among the three stakeholders, I propose to grant an interest free loan up to Rs. 2.5 crore to each ITI for upgradation and revision of courses. I seek the cooperation of State Governments in upgrading at least 300 ITIs every year, beginning 2007-08, under the PPP mode. I have kept aside Rs. 750 crore for this purpose.

Employment for the Physically Challenged

105. Among the disadvantaged sections of the society are physically challenged persons. They face difficulties in obtaining regular employment. In order to incentivise employers in the organised sector to provide regular employment, I propose a scheme whereunder Government will reward the employer once the physically challenged employee is regularised and is enrolled under the Employees Provident Fund (EPF) and the Employees State Insurance (ESI). Under the scheme, Government will reimburse the employer's contribution to the EPF and ESI for the first three years. Government is ready to support the creation of about 100,000 jobs every year for physically challenged persons with a salary limit of Rs. 25,000 per month. I estimate the cost to Government at Rs. 150 crore per annum rising to Rs. 450 crore per annum when the scheme is fully rolled out. I have therefore earmarked Rs. 1,800 crore.

Debt Management Office

106. World over, debt management is distinct from monetary management. The establishment of a Debt Management Office (DMO) in the Government has been advocated for quite some time. The fiscal consolidation achieved so far has encouraged us to take the first step. Accordingly, I propose to set up an autonomous DMO and, in the first phase, a Middle Office will be set up to facilitate the transition to a full-fledged DMO.

Development Cooperation

107. In keeping with India's growing stature in international affairs, we must willingly assume greater responsibility in promoting development in other developing countries. At present, India extends development cooperation through a number of Ministries and agencies and the total sum is about US$ 1 billion per annum. It is felt that all activities relating to development cooperation should be brought under one umbrella. Accordingly, Government proposes to establish the India International Development Cooperation Agency (IIDCA). The Ministries of External Affairs, Finance and Commerce and other stakeholders will be represented on IIDCA.

Climate Change

108. India is not a significant contributor to green house gas (GHG) emissions, nor will it be so in the foreseeable future. Nevertheless, in line with the principle of "common but differentiated responsibility", India has taken important steps to mitigate GHG emissions and adapt to climate change impact. India has also strongly promoted the clean development mechanism (CDM) under the Kyoto Protocol and has the world's largest number of CDM projects. Nevertheless, India is among the countries more vulnerable to climate change. Hence, Government proposes to appoint an expert committee to study the impact of climate change on India and identify the measures that we may have to take in the future.

Commonwealth Games

109. India bid for and won for the city of Delhi the Commonwealth Games 2010. The nation was filled with pride when, under the guidance of Shri Rajiv Gandhi, we successfully hosted the Asian Games in 1982. We owe it to our people to make the Commonwealth Games an equally memorable event. I propose to provide in 2007-08 Rs. 150 crore to the Ministry of Youth Affairs and Sports and Rs. 350 crore to the Delhi Government for the Games. Similarly, I propose to provide Rs. 50 crore for the Commonwealth Youth Games, 2008 to be held in Pune.

History and Culture

110. As we celebrate the 150th year of the First War of Independence and the centenary year of the Satyagraha Movement, our thoughts go to the institutions that continue the work of Gandhiji and other constructive work. I intend to set apart Rs. 30 crore for four institutions whose work we gratefully acknowledge. These are Sabarmati Ashram, Ahmedabad; Sevagram Ashram, Wardha; Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune; and Rajendra Smriti Sanghrahalaya, Patna. I also intend to provide Rs. 20 crore to reposition the Nehru Memorial Museum and Library, Delhi, as a major centre of intellectual activity.

111. The Ministry of Culture purposes to engage scholars from India and foreign institutions to work on specific projects. The terms of engagement will provide freedom and flexibility to the scholars. I intend to make an initial grant of Rs. 5 crore to encourage this effort.

Institutions of Excellence

112. As in the last two years, I purpose to make a special grant of Rs. 100 crore to recognise excellence. Government has selected the Govind Ballabh Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar and the Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, and each will be given Rs. 50 crore.

XI. PUBLIC FINANCE

113. Thanks to the Fiscal Responsibility legislations, the Central Government and the State Governments have regained lost fiscal ground. Rs. 110,628 crore of State's debt has been consolidated. Twenty States have availed of the benefit of debt waiver to the tune of Rs. 8,575 crore.

114. In 2006-07, the Centre will give to the States as their share of taxes and duties Rs. 120,377 crore. In 2007-08, this amount will increase to Rs. 142,450 crore. Besides, total grants and loans, both under Plan and Non-Plan, to States and Union Territories will increase from Rs. 90,521 crore in 2006-07 to Rs. 106,987 crore in 2007-08.

VAT, CST and a Roadmap towards GST

115. VAT has proved to be an unqualified success. VAT revenues of the implementing States increased by 13.8 per cent in 2005-06 and by 24.3 per cent in the first nine months of 2006-07. The next logical step is to phase out Central Sales Tax (CST). I am glad to report that the Central Government has reached an agreement with State Governments to phase out CST. Consequently, the CST rate will be reduced from 4 per cent to 3 per cent with effect from April 1, 2007. I have provided Rs. 5,495 crore for compensation for losses, if any, on account of VAT and also on account of CST.

116. I wish to record my deep appreciation of the spirit of cooperative federalism displayed by State Governments and especially their Finance Ministers. At my request, the Empowered Committee of State Finance Ministers has agreed to work with the Central Government to prepare a roadmap for introducing a national level Goods and Services Tax (GST) with effect from April 1, 2010.

117. So far as the Central Government is concerned, the fiscal consolidation is proceeding according to the FRBM Act. Based on Revised Estimates, I am happy to report that the revenue deficit for the current year will be 2.0 per cent (against a BE of 2.1 per cent) and the fiscal deficit will be 3.7 per cent (against a BE of 3.8 per cent).

XII. BUDGET ESTIMATES FOR 2007-08

118. I turn to the Budget Estimates for 2007-08.

Plan Expenditure

119. I estimate Plan Expenditure for 2007-08 at Rs. 205,100 crore. As a proportion of total expenditure (net of the SBI share acquisition), Plan Expenditure will be 32.0 per cent.

Non-Plan Expenditure

120. Non-Plan Expenditure in 2007-08 (net of the SBI share acquisition) is estimated at Rs. 435,421. The increase over 2006-07 is only 6.5 per cent.

Revenue Deficit and Fiscal Deficit

121. Mr. Speaker, Sir, in the Budget Estimates for 2007-08, the total expenditure is estimated at Rs. 680,521 crore (including Rs. 40,000 crore for the SBI share acquisition). The total revenue receipts of the Central Government are projected to be Rs. 486,422 crore and the revenue expenditure to be Rs. 557,900 crore. Consequently, the revenue deficit is estimated at Rs. 71,478 crore which is 1.5 per cent of the GDP. The fiscal deficit is estimated at Rs. 150,948 crore, which is 3.3 per cent of the GDP. I am happy to report that we are on course to achieve the FRBMA targets.

653 GI/07—9

Part-B

XIII. TAX PROPOSALS

122. Mr. Speaker, I shall now present my tax proposals.

123. The UPA Government promised that "tax rates will be stable and conducive to growth, compliance and investment". The increase in gross tax revenue is proof of a promise fulfilled. While we have raised more tax revenue, we have also left more money in the hands of the people as savings and for investment.

124. Gross tax revenue has grown by 19.9 per cent, 20.0 per cent and 27.8 per cent in the first three years of this Government. The tax to GDP ratio has increased from 9.2 per cent in 2003-04 to 11.4 per cent in 2006-07. We intend to keep our tax rates moderate and stable and administer the tax laws in a tax payer-friendly manner.

Indirect Taxes

125. I shall begin with indirect taxes. Firstly, customs duties.

126. In January 2007, Government announced wide ranging reductions in tariffs. Import duties on capital goods, project imports, metals and specified inorganic chemicals were reduced by 2.5 percentage points and, in some cases, by 5 percentage points. Duties on some edible oils were reduced by 10 to 12.5 percentage points.

127. In order to take one more step towards comparable East Asian rates, I propose to reduce the peak rate for non-agricultural products from 12.5 per cent to 10 per cent.

128. I propose to reduce the duties on most chemicals and plastics from 12.5 per cent to 7.5 per cent.

129. The duty on prime steel is 5 per cent. Seconds and defectives augment supply. Keeping in mind the need for a differential, I propose to reduce the duty on seconds and defectives of steel from 20 per cent to 10 per cent.

130. I propose to fully exempt from duty all coking coal irrespective of the ash content.

131. Last year, I reduced the excise duty on all man-made fibres and yarns from 16 per cent to 8 per cent. To further encourage this industry, I propose to reduce the customs duty on polyester fibers and yarns from 10 per cent to 7.5 per cent. Consequently, the customs duty on raw-materials such as DMT, PTA and MEG will also be reduced from 10 per cent to 7.5 per cent.

132. Another industry that is a growth-end employment-driver is gem and jewellery. I propose to bring down the duty on cut and polished diamonds from 5 per cent to 3 per cent; on rough synthetic stones from 12.5 per cent to 5 per cent; and on unworded corals from 30 per cent to 10 per cent.

133. I propose to fully exempt dredgers from import duty.

134. To augment irrigation facilities and processing of agricultural products, I propose to reduce the duty on drip irrigation systems, agricultural sprinklers and food processing machinery from 7.5 per cent to 5 per cent.

135. While specified medical equipment attract a concessional duty of 5 per cent, other equipment are taxed at 12.5 per cent. I propose to bring down the general rate of import duty on medical equipment to 7.5 per cent.

136. In order to make edible oils more affordable, I propose to exempt crude as well as refined edible oils from the additional CV duty of 4 per cent. I also propose to reduce the duty on sunflower oil, both crude and refined, by 15 percentage points.

137. I have good news for cat and dog lovers. I propose to reduce the duty on pet foods from 30 per cent to 20 per cent.

138. I propose to reduce the duty on watch dials and movements as well as umbrella parts from 12.5 per cent to 5 per cent.

139. In order to promote research and development, I propose to extend the concessional rate of 5 per cent duty available to public funded research institutions to all research institutions registered with the Directorate of Scientific and Industrial Research. For the pharmaceutical and biotechnology sector, I propose to reduce the duty on 15 specified machinery from 7.5 per cent to 5 per cent.

140. Import of aircraft, including helicopters, by Government and scheduled airlines is, at present, exempt from all duties, and that position will continue. However, there is no reason to allow the exemption to other private importers. Hence, I propose to levy an import duty of 3 per cent, which is the WTO bound rate, on all private import of aircraft including helicopters. Such import will also attract countervailing duty and additional customs duty.

141. The Hoda Committee has submitted a report on mineral policy. Taking a leaf out of the report, and in order to conserve our natural resources as well as to raise revenue, I propose to impose an export duty of Rs. 300 per metric tonne on export of iron ores and concentrates and Rs. 2000 per metric tonne on export of chrome ores and concentrates.

142. I shall now turn to my proposals on excise duties and service tax.

143. There will be no change in the general CENVAT rate or in the service tax rate.

144. On February 15, 2007, Government reduced the price of petrol and diesel by Rs. 2 per litre and Rs. 1 per litre, repectively. I had agreed that the Revenue will bear a part of the burden. Hence, I propose to redcuce the *ad valorem* component of excise duty on petrol and diesel from 8 per cent to 6 per cent.

145. Keeping in mind the special needs of several sectors and the interest of the consumers, I propose to grant relief from excise duty in deserving cases, especially job creating sectors:

- I propose to raise the exemption limit for Small Scale Industry (SSI) from Rs. 1 crore to Rs. 1.5 crore.
- The food processing sector is poised to achieve high growth. Concessions were extended last year to several item of food. This year, I propose to fully exempt from excise duty biscuits whose retail sale price does not exceed Rs. 50 per kilogram. I also propose to fully exempt from excise duty all kinds of food mixes including instant mixes. I can no longer be accused of being partial to idli and dosa mixes.
- I propose to reduce excise duty on umbrellas and parts of footwear from 16 per cent to 8 per cent.
- Plywood helps to save wood. Hence, I propose to reduce excise duty on plywood from 16 per cent to 8 per cent.
- Biodiesel will greatly reduce our dependence on fossil fuels. Hence, I propose to fully exempt biodiesel from excise duty.

146. To provide access to pure drinking water for households and communities, I propose to fully exempt from excise duty water purification devices operating on specified membrane based technologies as well as domestic water filters not using electricity.

147. Pipes used for carrying water from a water supply plant to a storage facility are exempt from excise duty. I propose to extend the exemption to all pipes of diameter exceeding 200 mm used in water supply systems.

148. There has been a significant increase in the retail price of cement. Last year, at this time, a bag of 50 kilogram was sold at a Maximum Retail Price (MRP) of Rs. 190 or less which, I understand, is a remunerative price. I propose to reward cement manufactures who hold the price line and tax those who do not. Accordingly, I propose to reduce the present rate of excise duty of Rs. 400 per metric tonne to Rs. 350 per metric tonne on cement which is sold in retail at not more than Rs. 190 per bag. On cement that has a higher MRP, the excise duty will be Rs. 600 per metric tonne.

149. I strongly support the campaign "say not to tobacco". Hence, I propose to increase the specific rates of excise duty on cigarettes by about 5 per cent. Similarly, excise duty (excluding cess) on biris, which was last fixed in 2001, will be raised from Rs. 7 to Rs. 11 per thousand for non-machine made biris and from Rs. 17 to Rs. 24 per thousand for machine made biris. There is an exemption from excise duty for unbranded biris up to 20 lakh biris in a year. Complaints have been received of misuse of the exemption. This exemption will henceforth be available subject to fulfilment of the condition of declaration with the Department of Central Excise and regular monitoring.

150. Pan masala containing tobacco will continue to bear an excise duty of 66 per cent. However, in the case of pan masala not containing tobacco, the duty will be reduced from 66 per cent to 45 per cent. I also propose to withdraw the exemption for pan masala containing tobacco and other tobacco products that is now given to units in the North Eastern States.

151. Based on a comprehensive review of exemptions and having posted them on the website and having invited comments, I propose to remove certain excise duty exemptions which are redundant or have outlived their utility.

152. I propose to raise the exemption limit for small service providers from Rs. 4000,000 to Rs. 800,000. Consequently, 200,000 assessees out of a total of 400,000 assessees will go out of the service tax net. The revenue loss will be Rs. 800 crores, but I am happy to give away this sum in the interest of the small service provider and the consumer.

153. While I bid goodbye to 200,000 assessees, I welcome the new assessees who will be brought into the fold. I propose to extend service tax to :

- Services outsourced for mining of mineral, oil or gas;
- Renting of immovable property for use in commerce or business; however, residential properties, vacant land used for agriculture and similar purposes, land for sports, entertainment and parking purposes, and immovable property for educational or religious purposes will be excluded;
- Development and supply of content for use in telecom and advertising purposes;
- Asset management services provided by individuals; and
- Design services.

154. State Government levy a tax on the transfer of property in goods involved in the execution of a works contract. The value of services in a works contract should attract service tax. Hence, I propose to levy service tax on services involved in the execution of a works contract. However, I also propose an optional composition scheme under which service tax will be levied at only 2 per cent of the total value of the works contract.

155. I propose to exempt service tax on services provided by Resident Welfare Associations to their members who contribute Rs. 3000 or less per month for services rendered.

156. In order to encourage innovation, I propose to exempt from service tax all services provided by technology business incubators. Similarly, their incubatees whose annual business turnover does not exceed Rs. 50 lakhs will be exempt from service tax for the first three years.

157. To make India a preferred destination for drug testing, I propose to exempt clinical trial of new drugs from service tax.

158. The scope of some services that are currently taxed is being expanded or redefined. However, I shall not burden the House with the details.

159. The telecommunications industry has repeatedly requested that the multifarious taxes, charges and fees applicable to the industry should be unified and a single levy on revenue should be collected. The request merits consideration. Hence, I propose to request the Department of Telecommunications to constitute a committee to study the present structure of levies and make suitable recommendations to Government.

Direct Taxes

160. I shall now move to direct taxes.

161. In the current year, there has been better tax complaince by individuals. I hope this trend will continue.

162. The current slabs and rates of personal income tax (PIT) were introduced only two years ago. They constitute a moderate tax regime. A comprehensive review should await the proposed Income Tax code which will be introduced in Parliament this year. Nevertheless, without altering the rates. I am inclined to consider giving some relief to tax payers, especially in view of the cooperation they have extended to the Department of Revenue. Accordingly, I propose that :

- the threshold limit of exemption in the case of all assessees be increased by Rs. 10,000, thus giving every assessee a relief of Rs. 1,000;
- consequently, in the case of a woman assessee, the threshold limit be increased from Rs. 135,000 to Rs. 145,000, giving her a relief of Rs. 1,000;
- the threshold limit of exemption in the case of a senior citizen be increased from Rs. 185,000 to 195,000, giving him or her a relief of Rs. 2,000 ; and

- the deduction in respect of medical insurance premium under Section 80D be increased to a maximum of Rs. 15,000 and in the case of a senior citizen, a maximum of Rs. 20,000.

163. On the corporate income tax (CIT) side too, there has been better compliance. Consequently, I propose to keep the same rate of CIT with one important modification. In order to encourage small and medium enterprises to invest and grow. I propose to remove the surcharge on income tax on all firms and companies with a taxable income of Rs. 1 crore or less. This will benefit about 1,200,000 firms and companies.

164. Profit-making cooperative banks, other than primary societies and primary banks (i.e., PACs and PCARDBs), have been brought on par with other banks. However, I have noticed some anomalies and I propose to correct them in the interest of the cooperative banks. Accordingly, the benefit of Section 36(1)(viii) will be available to cooperative banks. Likewise, cooperative banks will also be allowed deduction in respect of provision for bad and doubtful debts under Section 36(1)(viia). Amalgamation and de-merger of banking companies is tax neutral and this benefit will be extended to cooperative banks.

165. Section 80-IA of the Income Tax Act lists the infrastructure facilities that are entitled to tax concessions. There are some obvious claimants to this benefit. One is cross country natural gas distribution network, including gas pipeline and storage facilities integrated to the network. The second is navigation channel in the sea. I propose to extend the tax concession to these two facilities.

166. In order to facilitate the creation of urban infrastructure, I propose to allow issue of tax-free bonds through State Pooled Finance Entities formed for raising funds for a group of urban local bodies.

167. Last year, I had constituted an expert body to advise the Government on tax policy in respect of the gem and jewellery industry. Taking into account its recommendations, the best international practices and the need for a simple tax regime, I proposed to introduce a benign assessment procedure for assessees engaged in diamond manufacturing and trading who declare profits from such activities at 8 per cent or more of the turnover. Instructions in this regard will issue shortly.

168. We will require 20,000 more hotel rooms for the Commonwealth Games. Hence, I propose a five-year holiday from income tax for two, three or four star hotels as well as for convention centres with a seating capacity of not less than 3,000. They should be completed and begin operations in the National Capital Territory of Delhi or in the adjacent districts of Faridabad, Gurgaon, Ghaziabad or Gautam Budh Nagar during the period April 1, 2007 to March 31, 2010.

169. Section 35(2AB) allows a weighted deduction of 150 per cent for expenditure relating to in-house research and development. I propose to extend the concession for five more years until March 31, 2012.

170. Undertakings in Jammu and Kashmir presently enjoy a tax holiday that is due to end on March 31, 2007. Considering the importance of promoting further investment in that State, I propose to extend the benefit for another five years up to March 31, 2012.

171. E-filing of corporate returns introduced this financial year has been a resounding success. Until January 31, 2007, 301,736 returns were electronically filed by corporates. Our analysis shows that the effective rate of tax paid by all corporates, thanks to numerous tax concessions and exemptions—several of them well-intended was only 19.2 per cent. In 1996-97, we intruduced the Minimum Alternate Tax (MAT) for companies with book profits, and its purpose is to bring about horizontal equity in taxation. MAT should therefore apply, as far as possible, to all corporate incomes. Hence, I propose to extend MAT to income in respect of which deduction is claimed under Sections 10A and 10B of the Income Tax Act.

172. I also propose to partially modify a deduction that is available to certain companies. Without altering the overall limit of the special reserve equal to twice the net worth under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, I propose to stretch out the period by restricting the deduction to 20 per cent of the profits each year and limit the benefit to banks and certain financial corporations.

173. Venture capital funds are a useful source of risk capital, especially for start-up ventures in the knowledge-intensive sectors. Since such funds enjoy a pass-through status, it is necessary to limit the tax benefit to investments made in truly deserving sectors. Accordingly, I propose to grant pass-through status to venture capital funds only in respect of investments in venture capital undertakings in biotechnology; information technology relating to hardware and software development; nanotechnology; seed research and development; research and development of new chemical entities in the

pharmaceutical sector; dairy industry; poultry industry; and production of bio-fuels. In order to promote business tourism, I also propose to allow this benefit to venture capital funds that invest in hotel-cum-convention centres of a certain description and size.

174. In December 2006, I put a limit of Rs. 50 lakh per investor per year with respect to capital gains bonds issued by NHAI and REC under Section 54EC of the Income Tax Act. As a result, many small investors could obtain these bonds and save on capital gains. I propose to continue this provision and, accordingly, I propose to amend Section 54EC to that effect.

175. I propose to expand the tax base of capital gains to include certain works of art.

176. I believe that my direct tax proposals have brought about more horizontal equity. It is also necessary to improve vertical equity. Having regard to the capacity to pay, I propose to raise the rate of dividend distribution tax from 12.5 per cent to 15 per cent on dividents distributed by companies.

177. Dividends distributed by money market mutual funds and liquid mutual funds enjoy concessional tax rates giving rise to huge arbitrage opportunities. I propose to address this distortion by raising the dividend distribution tax on dividends paid by such entities to 25 per cent for all investors.

178. Fringe Benefit Tax (FBT) had now stabilized. I have received a few representations regarding some aspects of sales promotion. Hence, I propose to clarify the doubts by excluding expenditure on free samples as well as expenditure on displays from the scope of FBT.

179. A number of companies provide fringe benefits to employees through Employees' Stock Option Plan (ESOP). I propose to bring ESOPs under FBT. The value of the fringe benefit will be determined, in accordance with a prescribed method, on the date of exercise of the option.

180. The Banking Cash Transactions Tax (BCTT) continues to be an extremely useful tool to track unaccounted monies and trace their source and destination. It has led the Income Tax Department to many money laundering and hawala transactions. Having regard to the experience gained, I propose to exclude cash withdrawals by the Central and State Governments from the scope of BCTT. Further, I propose to raise the exepmtion limit for individuals and HUFs from Rs. 25,000 to Rs. 50,000. As other instruments become more effective, I thank it would be possible to review BCTT next year.

181. I have a proposal regarding the cess for education. While the cess of 2 per cent on all taxes to fund basic education will remain. I propose to levy an additional cess of 1 per cent on all taxes to fund secondary education and higher education and the expansion of capacity by 54 per cent for reservation for socially and educationally bankward classes.

182. Finally, there is a small matter which has large beneficial consequences. In 2001, 'Aviation Turbine Fuel sold to turbo-prop aircraft' was included in the list of declared goods under Section 14 of the CST Act. Turbo-prop aircraft have been replaced by new generation small aircraft which have taken air services to smaller airports and to the remote parts of the country. Hence, I propose to amend the provision to cover all small aircraft with maximum takeoff mass of less than 40,000 kgs. operated by scheduled airlines.

183. Along with tax reforms, the Government has laid great emphasis on tax administration. The cost of collection of taxes in India is among the lowest in the world. A number of administrative goals have been set for 2007-08. These include expanding the coverage of Annual Information Returns, extending the Refund Banker System to more areas, extending the e-payment facility through more banks, making electronic filing of returns mandatory for more categories of assessees and creating new Large Tax Payer Units.

184. My tax proposals on direct taxes are estimated to yield a gain of Rs. 3,000 crore. On the indirect taxes side, the proposals are revenue neutral.

XIV. Conclusion

185. Mr. Speaker, Sir, our human and gender development indices are low not because of high growth but because growth is not high enough. Faster economic growth has given us, once again, the opportunity to unfurl the sails and catch the wind. Without growth, I could not have given a new thrust to agriculture. I could not have given relief to the small tax-payer, the small service provider and to small scale industry. I could not have promised 100,000 scholarships or 100,000 jobs for the physically challenged. I could not have promised a massive ground water recharge programme or social security for rural landless households.

186. The UPA Government has delivered on the promise of savings and investment, and will deliver on the promise of encouraging more savings and translating the savings into more investment. It has delivered on the promise of growth, and will deliver on the promise of making growth more inclusive. I believe that, given a right mix of policies, the poor will benefit from growth that is driven by savings and investment and that is more inclusive. As Dr. Muhammad Yunus, the Nobel laureate, said, "Faster growth rate is essential for faster reduction in poverty. There is no other trick to it."

187. Sir, with these words, I commend the Budget to the House.

L. M. VAS, Jt. Secy. (Budget)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.